नई दिल्ली
शुक्रवार
04 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 01
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

# सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158

बेंगलुरु पहुंचे सम्राट चौधरी और संजय सरावगी,...पेज-05

पश्चिमी यूपी में राजनीतिक फायदे के लिए...पेज-08

## एक नजर

### जीडीपी की बढ़ी दर आंकड़ों के खेल का परिणाम : कांग्रेस

**नई दिल्ली,एजेंसी।** कांग्रेस ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही में जीडीपी की 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर को आधार वर्ष में किए गए बड़े संशोधनों, कम डिफ्लेटर और पिछले वर्षों के आंकड़ों में करीब 43 लाख करोड़ रुपये की कटौती का परिणाम बताते हुए कहा कि यह आर्थिक विकास की वास्तविक तस्वीर नहीं, बल्कि आंकड़ों के साथ किए गए खेल का नतीजा है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने गुरुवार को यहां एक बयान में बताया कि अप्रैल-जून 2025 तिमाही के जीडीपी आंकड़े चार बार संशोधित किए गए और करीब 86 लाख करोड़ रुपये के अनुमान को घटाकर लगभग 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 से पिछले चार वर्षों के आंकड़ों में भी इसी तरह संशोधन हुआ है और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के अनुमानित आकार में करीब 43 लाख करोड़ रुपये की कमी की गई है। श्री रमेश ने कहा कि पिछले वर्ष के आधार आंकड़े को नीचे करने से इस वर्ष की वृद्धि दर स्वाभाविक रूप से अधिक दिखाई देती है। उन्होंने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के आकलन का हवाला देते हुए कहा कि आधार आंकड़े में यह बदलाव नहीं किया गया होता तो इस तिमाही की नाममात्र वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत के बजाय करीब 2.6 प्रतिशत होती और महंगाई का प्रभाव हटाने के बाद वास्तविक वृद्धि लगभग शून्य रह जाती।कांग्रेस नेता ने विनिर्माण और निजी खपत के आंकड़ों को भी सरकार के दावे के विपरीत बताया और कहा कि श्री गर्ग के आकलन के अनुसार विनिर्माण जीवीए में 5.2 प्रतिशत और निजी खपत में 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने विनिर्माण गतिविधियों में सुस्ती और लोगों की घटती क्रय शक्ति का भी उल्लेख किया। श्री रमेश ने वित्त मंत्री से पूछा कि चार वर्षों के जीडीपी अनुमानों में कुल 43 लाख करोड़ रुपये की कमी क्यों की गई, नई पद्धति के किन घटकों से इतना बड़ा बदलाव आया और इसे तैयार करने की प्रक्रिया क्या थी। उन्होंने यह भी पूछा कि नई पद्धति तैयार करते समय किन लोगों से परामर्श किया गया तथा वास्तविक जीडीपी की गणना में महंगाई के प्रभाव को कम करने वाली अपस्फीति पद्धति अपनाने का आधार क्या है।

### राजनाथ ने रक्षा कूटनीति पर 'रक्षा' दस्तावेज जारी किया

**नई दिल्ली।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यहां रक्षा कूटनीति पर 'रक्षा' दस्तावेज का विमोचन किया जिसमें अगले 10 वर्षों के लिए वैश्विक रक्षा साझेदारियों के संबंध में भारत के रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक विकास को बढ़ावा मिल सके। 'रक्षा' दस्तावेज में रणनीतिक साझेदारी, क्षमता विकास, स्वदेशी रक्षा निर्यात और समुद्री सुरक्षा को प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। इसके तहत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग मजबूत करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा मित्र देशों के साथ रक्षा के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत में निर्मित रक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर देश को विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। दस्तावेज में हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा प्रदाता और पहले मदद करने वाले देश के रूप में भूमिका को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

# भारत-बेल्जियम साझेदारी में नयी गति, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य: मोदी

## नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से द्विपक्षीय वार्ता की

**नई दिल्ली,एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत और बेल्जियम की साझेदारी में नयी गति आयी है और दोनों देशों के बीच सहयोग पारंपरिक क्षेत्रों से बढ़कर रक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीति क्षेत्रों तक पहुंच गया है जिसे आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे आर्थिक संबंधों के लिए नये अवसर खुले हैं। बेल्जियम की कंपनियों के लिए भारत में निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र बनाया गया है और भारत-बेल्जियम व्यापार मंच को नियमित तंत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। मोदी ने भारत यात्रा पर आये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से गुरुवार को यहां द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद श्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और आज की चर्चा से दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सहयोग अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का अहम हिस्सा है। लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और गहरे जनसंपर्क भारत और बेल्जियम को स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजनाओं में से एक को विकसित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है और पिछली तिमाही में इसमें 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को उन्होंने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे आर्थिक संबंधों के लिए नये अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि बेल्जियम की कंपनियों के लिए भारत में निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र बनाया गया है और भारत-बेल्जियम व्यापार मंच को नियमित तंत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। दोनों देशों की वित्तीय, फिन टेक और नियामक संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा। इन पहलों के माध्यम से अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को संबंधों का प्रमुख स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। सरकारों और रक्षा उद्योगों के बीच हुए समझौतों से रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और सह-उत्पादन के नये अवसर खुलेंगे। खुफिया जानकारी साझा करने और अपराध के खिलाफ सहयोग को भी मजबूत किया जायेगा। श्री मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर हुए समझौता ज्ञापन से सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को गति मिलेगी। महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बेल्जियम की विशेषज्ञता और भारत के पैमाने को एक दूसरे का पूरक बताते हुए उन्होंने कहा कि बेल्जियम के आईएमईसी संस्थान को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने स्टार्ट-अप के बीच संपर्क मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण बढ़ाने पर सहमति बनायी है। विश्वविद्यालय और अनुसंधान सहयोग को मजबूत किया जायेगा तथा प्रतिभा आवागमन के लिए जल्द ही प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता किया जायेगा। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बेल्जियम कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्ष की शीघ्र समाप्ति तथा शांति के सभी प्रयासों का दोनों देश समर्थन करते हैं। आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा,' यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।'

# नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ईडी की बड़ी कार्रवाई

● दक्षिण भारत में 30 ठिकानों पर तलाशी

**नई दिल्ली,एजेंसी।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों से जुड़े आठ मामलों में दक्षिण भारत में एक साथ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ईडी की विभिन्न जोनल टीमों की ओर से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में कुल 30 ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ईडी के अनुसार, दक्षिण क्षेत्र के सभी जोन में एक साथ की जा रही इस कार्रवाई के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े कथित धन के लेनदेन से संबंधित आठ अलग-अलग मामलों की जांच की जा रही है।

तलाशी के दौरान एजेंसी का उद्देश्य मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों से जुड़े धन, संपत्तियों, बैंक खातों, दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का पता लगाना है। आगे की जांच जारी है। तमिलनाडु के निसारदीन, कासिलिंगम और अन्य से जुड़े मामले में 11 जून 2024 को एनसीबी ने मंडपम शरणार्थी शिविर में रह रहे श्रीलंकाई नागरिक एन. अजनथन और के. मधुशन को पकड़ा था। उनके पास से 1.470 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुआ था। 14 जून 2024 को चेन्नई के मन्नाडी स्थित अंगप्पा नायकेन स्ट्रीट के दुकान संख्या 193/138 पर के. कृष्णा कुमारी को मोहम्मद रिजालुदीन से रुपये लेते हुए पकड़ा गया। वहां से 1.29 करोड़ रुपये से अधिक भारतीय मुद्रा, 30 हजार अमेरिकी डॉलर और 5,030 श्रीलंकाई रुपये बरामद किए गए। ईडी के अनुसार, उक्त परिसर का संचालन दुबई में रह रहे एस. निसारदीन की ओर से मोहम्मद रिजालुदीन कर रहा था और इसका इस्तेमाल अनधिकृत हवाला लेनदेन के लिए किया जा रहा था। इस मामले में चेन्नई और रामनाथपुरम जिले में

दो ठिकानों पर तलाशी चल रही है। तमिलनाडु के सैयद इब्राहिम, बयसुल रहमान और अन्य से जुड़े मामले में 24 जुलाई 2024 को एनसीबी ने चेन्नई के किलाम्बक्कम बस टर्मिनस के पास बयसुल रहमान को पकड़ा था।

उसके पास से 5.970 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुआ। एनसीबी ने इस मामले में 39.38 लाख रुपये नकद, 586 ग्राम सोना और एक किलोग्राम चांदी भी जब्त की थी। ईडी के अनुसार, इस मामले में चेन्नई और रामनाथपुरम के बीच हवाला और नकदी लेनदेन से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली में दो ठिकानों पर तलाशी जारी है। उदय कुमार और अन्य से जुड़े तमिलनाडु के मामले में 10 दिसंबर 2023 को एनसीबी ने चेन्नई के मन्नाडी स्थित होटल व्हाइट पैलेस के कमरा संख्या 109 में श्रीलंकाई नागरिक एस. उदय कुमार के कब्जे से दो किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया था। जांच में सामने आया कि उसे श्रीलंका के राजन उर्फ मदन के निर्देश पर यह खेप प्राप्त करने के लिए चेन्नई भेजा गया था। इसी मामले में एनसीबी ने अंबत्तूर स्थित वायरलेस ग्राउंड से 54.600 किलोग्राम मेथामफेटामाइन भी बरामद किया था। ईडी के अनुसार, इस मामले में छह ठिकानों पर तलाशी चल रही

# दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत

**नई दिल्ली,एजेंसी।** राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों की शर्त पर जमानत आदेश दिया है। कोर्ट ने 25 अगस्त को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि जैन की गिरफ्तारी केस दर्ज होने के 27 महीने बाद की गई, उन्हें सिर्फ एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

इस पर एसीबी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन आदतन अपराधी हैं। सत्येन्द्र जैन और दूसरे आरोपितों को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने जैन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने कहा था कि जैन को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई जो उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। एसीबी ने सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया था। इन आरोपितों को एसीबी की उस एफआईआर के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो 11 मई, 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं 7, 7, 9, 13 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 42, 409, 418, 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। सत्येंद्र जैन अक्टूबर, 2024 में तिहाड़ जेल से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल से बाहर आए थे। वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 872 दिन जेल में रहे थे। ईडी ने उन्हें 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। 18 अक्टूबर, 2024 को उन्हें ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी।

# अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल है केंद्र सरकार: शरद

**बारामती।** राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की असल समस्याओं को नज़रअंदाज़ करते हुए सब कुछ बहुत अच्छा होने की तस्वीर पेश कर रहे हैं। श्री पवार ने गुरुवार को कहा कि सरकार आर्थिक मंदी के संकेतों को अनदेखा कर रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, 'ज़मीनी हकीकत को दरकिनार कर दिया गया है। लोगों को अपनी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे और महंगाई की मार झेलनी होगी। कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ मामले वापस लेने के उच्चतम न्यायालय के हालिया फ़ैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला विद्यार्थियों की जायज़ मांगों से जुड़ा था।

# तरजीही दर की पेशकश के बाद ही अमेरिका के साथ व्यापार करार को अंतिम रूप देंगे: पीयूष गोयल

## कहा-अमेरिका से प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तरजीही दर की पेशकश पर ही बीटीए को अंतिम रूप देंगे

**नई दिल्ली,एजेंसी।** केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का अंतिम प्रारूप तभी घोषित किया जाएगा, जब भारत के प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अमेरिका तरजीही शर्तों की पेशकश करेगा, जिनसे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग देशों के मुकाबले स्पष्ट बढ़त मिल सके। गोयल वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित मुक्त व्यापार समझौतों पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, 'न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता जल्द ही लागू होगा और उसके बाद 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के साथ एफटीए भी लागू होगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही अमेरिका हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में हमें तरजीही दर देने में सक्षम होगा, हम बीटीए को अंतिम रूप देंगे और इसका अंतिम प्रारूप घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ऐसे देशों के साथ हैं, जिनका कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 60 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ये समझौते वैश्विक व्यापार के करीब दो-तिहाई हिस्से तक तरजीही पहुंच उपलब्ध कराएंगे।

गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का अंतिम प्रारूप तभी घोषित किया जाएगा, जब भारत के प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अमेरिका तरजीही शर्तों की पेशकश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ महीनों और दो-तीन वर्षों में कनाडा, मेक्सिको, चिली, मर्कोसुर, एसएसीयू (दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ), जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) और इजराइल के साथ भी एफटीए करेगा। मंत्री ने कहा कि भारत...ब्रिटेन, मॉरीशस, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते लागू कर चुका है। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मौजूदा व्यापार समझौतों की समीक्षा के प्रयासों से भारत को वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत हिस्से तक अपने प्रतिस्पर्धियों से कम दर पर पहुंच मिलेगी।

# दिल्ली में बनेगा मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम, सड़कें बार-बार खोदने की समस्या होगी समाप्त

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों की बार-बार खोदने को समाप्त के लिए मल्टी-यूटिलिटी डक्ट (एमयूडी) विकसित करेगी। इसके तहत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे, ताकि बिजली केबल, पानी और गैस की लाइनों, फायर-हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक यूटिलिटी सेवाओं के लिए इस उपयोग कर सकें। चांदनी चौक में इस पहल को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मल्टी-यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार-बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम हो जाएगी, यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी, नागरिकों

को होने वाली असुविधा घटेगी और सड़कों की संरचनात्मक मजबूती को भी बेहतर ढंग से बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकार ने यह निर्णय हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास की हमारी सोच केवल आज की जरूरतों तक सीमित नहीं है। हम ऐसी आधारभूत संरचना तैयार करना चाहते हैं, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और टिकाऊ हो। मल्टी-यूटिलिटी डक्ट इसी सोच का हिस्सा है। इससे अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होगा और दिल्ली में भूमिगत यूटिलिटी नेटवर्क के विकास के लिए एक अधिक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार होगी। साझा भूमिगत कॉरिडोर उपलब्ध होने से यूटिलिटी नेटवर्क के रखरखाव और भविष्य में उनके विस्तार का काम भी अधिक आसान और तेज हो सकेगा। साथ ही खुदाई के दौरान यूटिलिटी लाइनों को होने वाले आकस्मिक नुकसान की आशंका कम करने और विभिन्न नागरिक एवं यूटिलिटी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

# राजस्थान और उप्र के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों व मीडिया के प्रवेश पर रोक के खिलाफ जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

**नई दिल्ली,एजेंसी।** उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

इस याचिका में स्कूलों के भीतर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइवस्ट्रीमिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने प्रिया मिश्रा की इस याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की, 'हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। यह याचिका 'स्कूल ठीक करो' अभियान की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की

बुनियादी ढांचागत कमियों को उजागर करना है। याचिका में राजस्थान सरकार के 16 अगस्त के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें बाहरी लोगों के लिए सरकारी स्कूलों में प्रवेश करने और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या लाइवस्ट्रीमिंग करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याचिका में 19 अगस्त के अयोध्या प्रशासन के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बाहरी लोगों, यूट्यूबरों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को बिना अनुमति के परिषदीय स्कूलों में प्रवेश करने या तस्वीरें/वीडियो लेने पर रोक लगाई गई थी। राज्य के कई अन्य जिलों में भी ऐसे ही निर्देश जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बच्चों की गोपनीयता, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करने के राज्य के कर्तव्य को स्वीकार करते हुए भी, ये प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21-ए के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इन तर्कों पर याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया।

### प्रदर्शनकारी वकीलों से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों के साथ कथित मारपीट के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि इस घटना की स्वतंत्र जांच जरूरी है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय जाने को कहा। प्रशांत भूषण ने कहा कि वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधारों की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे।

# मुख्यमंत्री ने तेहखंड एटीएस का किया उद्घाटन, 50 ईवी बसों और दिल्ली-रेवाड़ी ई-बस सेवा को दिखाई झंडी

**सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार**

**नई दिल्ली।** दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को डीटीसी के तेहखंड डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) का उद्घाटन किया। उन्होंने हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही दिल्ली और रेवाड़ी के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डीटीसी की कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया।

इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह, दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार को सेफ्टी, सस्टैनबिलिटी, सीमलेस कनेक्टिविटी, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर लगातार काम करना होगा। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन सहित कई सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं। दिल्ली में बस नेटवर्क का विस्तार कर शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच संपर्क को और बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उस समय काम करने के बजाय काम की फिक्र और फिक्र का जिक्र अधिक किया जाता था। लंबे समय तक डीटीसी कर्ज में रहा, कर्मचारी परेशान रहे और ड्राइवर, कंडक्टर और अधिकारियों की समस्याएं उलझी रहीं। दिल्ली की जनता लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती रही, लेकिन वर्तमान सरकार के करीब डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में दिल्ली ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अब तक 18 लाख महिलाओं ने पिंक कार्ड बनवा लिए हैं। महिलाओं को पिंक कार्ड बनवाने के लिए 17 सितंबर तक यानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन तक, अतिरिक्त अवसर दिया गया है। इसके बाद पिंक टिकट की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपना पिंक कार्ड बनवाएं। मुख्यमंत्री ने डीटीसी तेहखंड डिपो में दिल्ली के दूसरे स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) का उद्घाटन किया। इससे पहले नंद नगरी डिपो में एटीएस शुरू किया जा चुका है। तेहखंड का यह 4-लेन स्वचालित परीक्षण केंद्र वाहनों की फिटनेस जांच को ज्यादा वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगा। इस एटीएस में भारी मोटर वाहनों के लिए 2 लेन, हल्के मोटर वाहनों के लिए एक लेन और दोपहिया वाहनों के लिए एक लेन होगी। इसकी वार्षिक परीक्षण क्षमता 72,000 वाहन होगी, जिसमें 52,000 भारी/हल्के मोटर वाहन और 20,000 दोपहिया वाहन शामिल हैं। पूरी परीक्षण प्रक्रिया स्वचालित होगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और वाहन फिटनेस आकलन में सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान डीटीसी बेड़े में शामिल की गई 50 नई 12-मीटर शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। दिल्ली सरकार ने हरित और सुविधाजनक अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए दिल्ली-रेवाड़ी शून्य-उत्सर्जन अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की शुरुआत की। यह सेवा धौला कुआं-गुरुग्राम-मानेसर-धारूहेड़ा-रेवाड़ी मार्ग पर चलेगी। धौला कुआं से रेवाड़ी तक लगभग 86 किलोमीटर की पूरी यात्रा का किराया 153 रुपये रखा गया है। ये बसें सुबह 6:05 से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगी, जबकि रेवाड़ी से धौला कुआं के लिए सेवाएं सुबह 9:35 से रात 9:25 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री ने डीटीसी हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। दोनों डिपो आनंद विहार बस अड्डे के नजदीक स्थित हैं।

## दिल्ली व असम के विधानसभा अध्यक्षों ने विधायी आधुनिकीकरण पर विचारों का किया आदान-प्रदान

**शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे**

**नई दिल्ली।** दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में असम विधानसभा के अध्यक्ष रणजीत कुमार दास से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों अध्यक्षों ने राज्य विधानसभाओं की बदलती भूमिका, विधायी आधुनिकीकरण, सतत विकास तथा संसदीय विरासत के संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दौरे के दौरान दोनों अध्यक्षों ने दिल्ली विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत केशव महाविद्यालय के जेन-जी विद्यार्थियों से भी संवाद किया।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत के लोकतंत्र और विकास के भविष्य को आकार देने में जेन-जी की भूमिका निर्णायक होगी तथा युवा नागरिकों को विधायी संस्थाओं के और करीब लाने की आवश्यकता है। गुप्ता ने कहा कि जब युवा अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समझते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करते हैं, तब लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। जेन जी केवल हमारे लोकतंत्र का भविष्य नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी इसकी एक महत्वपूर्ण आवाज है। असम विधानसभा अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने भी विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और विधानसभा के भ्रमण को लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हुए समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। दास ने कहा कि किसी विधानमंडल का दौरा करना और उसके भीतर से उसकी कार्यप्रणाली को समझना एक विशेष अवसर है।

युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विधानसभा भवन का निर्देशित भ्रमण भी कराया गया, जहां उन्हें दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली एवं उसके संस्थागत इतिहास से परिचित कराया गया। विद्यार्थियों को 'विठ्ठल भाई की गौरव गाथा' नामक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें विठ्ठलभाई पटेल के जीवन, योगदान एवं संसदीय विरासत को रेखांकित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक शिक्षा को कक्षा-कक्ष तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थियों को विधायिका को एक जीवंत लोकतांत्रिक संस्था के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव कराने तथा इसके संचालन से जुड़े लोगों के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान करना था। विजेंद्र गुप्ता ने रणजीत कुमार दास को दिल्ली विधानसभा में प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में भी जानकारी दी। इनमें विधानसभा की पूरी तरह पेपरलेस विधायी कार्यप्रणाली, पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनने की दिशा में जारी प्रयास तथा 'विधान साथी', विधानसभा का इन-हाउस एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म, शामिल हैं, जिसे विधायकों को विधायी सूचनाओं एवं जानकारी तक सुगम पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

## सौरभ भारद्वाज ने सत्येंद्र जैन को न्यायालय से जमानत मिलने के फैसले का किया स्वागत

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी (आआपा) के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पार्टी ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जमानत मिलने से सत्येंद्र जैन अब अपने परिवार के बीच लौट सकेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। उन्होंने कहा कि जैन को पंजाब में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों से जोड़ा गया था और उनकी गिरफ्तारी का असर चुनावी तैयारियों पर भी पड़ा। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित टेंडर मामले को लेकर भी सवाल उठाए। भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह आबकारी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का पक्ष रहा है, उसी तरह दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी पार्टी का मानना है कि आरोपों में दम नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मामले में जांच और आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद भी एसीबी की ओर से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के लिए एसीबी ने उनसे पूछताछ करने के बजाय सीधे उन्हें गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल भेज दिया। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर संतोष जताते हुए कहा कि अब सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेल बॉन्ड समेत आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जैन अपने परिवार के साथ घर लौट सकेंगे। भारद्वाज ने बताया कि जमानत मिलने के बाद सत्येंद्र जैन की मुलाकात उनकी पत्नी और बेटी से हुई।

## एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस के 11 सार्वजनिक शौचालयों के संचालन का समय बढ़ाकर मध्यरात्रि तक किया

**नई दिल्ली।** नागरिकों एवं आगंतुकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जन-सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने कनॉट प्लेस स्थित 11 सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं के संचालन का समय बढ़ाकर मध्यरात्रि तक करने का निर्णय लिया है। कनॉट प्लेस में कुल 23 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 11 सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं आम जनता के लिए मध्यरात्रि तक उपलब्ध रहेंगी। इनकी विस्तारित समय-सारिणी को 04 सितंबर, 2026 से लागू किया जाएगा।

एनडीएमसी के अध्यक्ष - श्री मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि कनॉट प्लेस देर रात तक नागरिकों, आगंतुकों और पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार रहता है। उन्होंने कहा, 'शाम और देर रात के समय कनॉट प्लेस आने वाले एवं यहां ठहरने वाले लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमसी ने 04 सितंबर से 11 सार्वजनिक शौचालयों के संचालन का समय बढ़ाकर मध्यरात्रि तक करने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में और अधिक सार्वजनिक शौचालयों को भी विस्तारित संचालन समय के अंतर्गत लाया जाएगा।' नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित कुल 23 सार्वजनिक शौचालयों में से प्रथम चरण में चिन्हित निम्नलिखित 11 सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं मध्यरात्रि तक उपलब्ध रहेंगी : - एस.बी.एस. मार्ग, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस। ई.एस.एस. के निकट, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस। मिडिल सर्किल, ए-ब्लॉक, आरआर-2 के निकट। मिडिल सर्किल, के-ब्लॉक, आरआर-4 एवं आरआर-5 के बीच, कनॉट प्लेस। मिडिल सर्किल, ई-ब्लॉक, आरआर-7 एवं सेंट्रल पार्क के बीच। डी-ब्लॉक के सामने, इनर सर्किल, कनॉट प्लेस। एफ-ब्लॉक के सामने, सेंट्रल पार्क, इनर सर्किल, कनॉट प्लेस। सुपर बाजार पार्किंग के निकट, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस। ईसीई हाउस, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस। मिडिल सर्किल, एफ-ब्लॉक, आरआर-1 के निकट। पंचकुइयां रोड एवं चेल्म्सफोर्ड रोड, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस। एनडीएमसी ने बताया कि कनॉट प्लेस में सार्वजनिक शौचालयों के संचालन का समय बढ़ाने की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देर शाम और रात्रि के समय भी आगंतुकों एवं आम जनता को आवश्यक नागरिक सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकें। परिषद् द्वारा नागरिकों से प्राप्त फीडबैक, जन-आवश्यकताओं तथा संचालन की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से अन्य सार्वजनिक शौचालयों में भी संचालन समय बढ़ाने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा।

## महिला पत्रकार से मारपीट की खबरों का दिल्ली पुलिस ने किया खंडन, बताया भ्रामक

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछने पर मारपीट की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर को गलत और भ्रामक बताया है। पुलिस ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि दो महिलाओं ने कार्यक्रम स्थल के पास अपनी स्कूटी खड़ी करके निर्धारित वीवीआईपी मार्ग को बाधित कर दिया था। वाहन हटाने और मार्ग को खाली करने के लिए बार-बार अनुरोध और निर्देश देने के बावजूद उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि वीवीआईपी मार्ग के सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दोनों महिलाओं को आगे की पूछताछ के लिए स्थानीय थाने ले जाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पर मारपीट का आरोप भी पूरी तरह से झूठ, भ्रामक और निराधार हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे असत्यापित और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने से बचें। उल्लेखनीय है कि 4पीएम नेटवर्क दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पर उनकी महिला पत्रकार से थाने में मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। सोशल मीडिया चैनल की पत्रकार ने थाने के भीतर से पूरे मामले पर वीडियो बनाकर दावा किया है कि उसके और उसके साथी के साथ मारपीट की गई ।

## डीयू कुलपति ने पहले कार्बन गार्डन का किया उद्घाटन, लगाया कल्पवृक्ष का पौधा

**नई दिल्ली।** दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने गुरुवार को वनस्पति विज्ञान विभाग में देश के पहले 'कार्बन गार्डन' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्बन गार्डन में एक कल्प वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस कार्बन गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि गार्डन का क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत ही अच्छी है। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि दुनिया भर में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। भारत में लगभग 17 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की समस्या लोगों के असंतुलित कार्यों से पैदा हुई है, उसका समाधान तकनीक से नहीं किया जा सकता उसके लिए दूसरे कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी को सतत समाधान का प्रयास करना होगा। योगेश सिंह ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है।

यहां प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, अगर सही कदम नहीं उठाए तो यह दिल्ली प्रदूषण की राजधानी बन जाएगी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में भी कार्बन गार्डन की स्थापना की जाने की अपील की। कुलपति ने कहा कि भारत में पश्चिमी देशों का अंधानुसरण किया जाता है जिसके कारण से पर्यावरण की समस्या ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाएं बनाते हुए देश की पर्यावरणीय परिस्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। डीयू वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख एवं कार्बन गार्डन के संस्थापक प्रो. दीनबंधु साहू ने भारत के पहले कार्बन गार्डन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्बन गार्डन बढ़ते वायु प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण से निपटने का एक समाधान है। उन्होंने बताया कि दो हजार वर्ग फुट के छोटे से इलाके में विकसित यह गार्डन भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाके के बीच एक मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क भी है। इस गार्डन में पौधों की 50 प्रजातियां हैं, जिनमें जड़ी-बूटियां, झाड़ियां और पेड़ शामिल हैं। इस अवसर पर कई विभागों के प्रमुखों सहित विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित काफी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।

## एमसीडी चुनाव में मचा बवाल: आप पार्षदों पर हंगामा, तोड़फोड़ और अभद्रता के गंभीर आरोप

**शबाना बेगम, सद्भावना टुडे**

**नई दिल्ली।** दिल्ली नगर निगम में 3,सितम्बर गुरुवार को समिति चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कथित हंगामे को लेकर राजनीतिक टकराव सामने आया। महापौर प्रवेश वाही ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर चुनाव प्रक्रिया बाधित करने, पीठासीन अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा बाद में महापौर कार्यालय में तोड़फोड़ और सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महापौर के अनुसार, तदर्थ अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के कोटे के कार्यान्वयन से संबंधित समिति की चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हुई थी। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद मौके पर पहुंचे और कथित रूप से हंगामा करते हुए चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डालने का प्रयास किया। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नामांकित नहीं किया गया था। इसके बावजूद चुनाव स्थल पर पहुंचकर प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी दल को चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति थी तो उसके लिए संवैधानिक और कानूनी माध्यम उपलब्ध हैं। महापौर ने आरोप लगाया कि चुनाव स्थल पर हंगामे के बाद कुछ आप पार्षद महापौर कार्यालय में पहुंचे, जहां कथित रूप से

दरवाजों और कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की किए जाने का भी आरोप लगाया। महापौर ने कहा कि उन्होंने स्वयं पार्षदों की बात सुनने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने इसे नगर निगम की संस्थागत गरिमा के विरुद्ध बताया।

महापौर प्रवेश वाही ने एक अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला उप महापौर के सामने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने कथित रूप से अपने कपड़े उतारने का प्रयास किया। महापौर ने इस कथित घटना को बेहद शर्मनाक और अमर्यादित बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों से सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तर की मर्यादा और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। महापौर ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार सभी को प्राप्त है, लेकिन हंगामा, अभद्र व्यवहार और संवैधानिक प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने का प्रयास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित होता है और किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। महापौर ने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को चुनाव प्रक्रिया पर कोई आपत्ति थी तो वे निर्धारित कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रिया का सहारा ले सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने के बाद हंगामे के माध्यम से प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के लिए गंभीर विषय है।

## वोटरों के एसआईआर फॉर्म में मौजूद सभी जानकारियों के लिए बीएलए जिम्मेदार नहीं : हाई कोर्ट

**नई दिल्ली।** दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को केवल उसी जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसकी वे पुष्टि कर सकते हैं। बीएलए को वोटर के एन्यूमरेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म में मौजूद सभी जानकारियों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही।

उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में निर्वाचन आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को निजी अंडरटेकिंग देनी जरुरी की गई है कि वे एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों को वेरिफाई करते हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंदर यादव और दिल्ली कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के लागू होने के पहले राजनीतिक दलों को 2002 के वोटर लिस्ट की प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी के अलावा फ्रोजन फोटो वोटर लिस्ट उपलब्ध करायी जाए। याचिका में निर्वाचन आयोग के 24 जून, 2025 के दिशा-निर्देश की धारा 9(डी)(4) को चुनौती दी गई है जिसके तहत बूथ लेवल एजेंट को एन्यूमरेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी को निजी तौर पर वेरिफाई करते हुए अंडरटेकिंग देने को कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट से संबंधित सूचना का वेरिफिकेशन करना बूथ लेवल अफसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों का एक वैधानिक कार्य है।

## आआपा ने पंजाब के किसानों से किया विश्वासघात, मोदी सरकार ने दिया हरसंभव सहयोग: तरुण चुघ

**नई दिल्ली।** भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं सांसद तरुण चुघ ने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। किसान मजदूर मोर्चा द्वारा 14 सितंबर से पंजाब के मंत्रियों और नेताओं के आवासों के बाहर धरना देने का फैसला भगवंत मान सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों के मुद्दों पर उसकी विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि किसानों का बार-बार सड़कों पर उतरने को मजबूर होना इस बात का प्रमाण है कि आप सरकार सत्ता में आने से पहले किसानों से किए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। तरुण चुघ ने कहा कि किसान मजदूर मोर्चा बासमती, मक्का, मूंग, सरसों और आलू की एमएसपी पर सरकारी खरीद की मांग कर रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें इन फसलों को लाभकारी कीमतों से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मोर्चे ने किसानों और कृषि मजदूरों की पूर्ण कर्जमाफी की मांग भी की है। गुरुवार को जारी अपने एक बयान में तरुण चुघ ने कहा कि ये मांगें भगवंत मान सरकार के किसान हितैषी होने के दावों की पोल खोलती हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले किसानों से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें बार-बार आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज किसान एमएसपी पर खरीद, कर्ज से मुक्ति और फसल नुकसान के खिलाफ सुरक्षा जैसी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लगातार एमएसपी बढ़ाकर, पीएम-किसान के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए फसल नुकसान के जोखिम से किसानों को सुरक्षा प्रदान की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जबकि पंजाब सरकार ने अभी तक इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया है।

## बारिश ने खोली दिल्ली की बदहाली की पोल, जलभराव और गड्ढों में फंसी राजधानी

**,सद्भावना टुडे, संवाददाता**

**नई दिल्ली।** राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, टूटी सड़कों और गहरे गड्ढों ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह-जगह पानी भरने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। इसी को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून से पहले किए गए तैयारियों के दावे भारी बारिश के बाद खोखले साबित हुए हैं।

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के निचले इलाकों में जलभराव के कारण बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। कई सड़कों पर पहले से मौजूद गहरे गड्ढे पानी में डूब गए हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। उनका आरोप है कि दिल्ली की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा राजधानी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली को 2047 तक विश्वस्तरीय राजधानी बनाने की बातें कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार वर्तमान दिल्ली की सड़कों, जल निकासी और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है तो 2047 के मास्टर प्लान का विकसित प्रारूप तैयार करने का दावा कितना

व्यावहारिक है? उन्होंने कहा कि राजधानी में सड़कें जगह-जगह टूट चुकी हैं और गड्ढों की समस्या लगातार बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 445 हॉटस्पॉट चिह्नित किए जाने का हवाला देते हुए यादव ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति का असर सीधे यातायात पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को एक से दो घंटे तक लग रहे हैं। देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किए गए गड्ढों की मरम्मत के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में बड़े पैमाने पर सड़कों की मरम्मत की गई होती तो आज बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों की तस्वीर इतनी खराब नहीं होती।

उन्होंने आईटीओ, मथुरा रोड, लक्ष्मी नगर, अरबिंदो मार्ग और एमबी रोड सहित दिल्ली के विभिन्न हिस्सों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनेक स्थानों पर सड़क की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। जलभराव के बीच गड्ढों का दिखाई न देना दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मानसून से पहले दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों को सड़क और जल निकासी से जुड़े कार्य पूरे करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बारिश के बाद जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल पानी निकासी, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही, दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भी जरूरी है। देवेंद्र यादव ने दिल्ली में बीमारियों के बढ़ते खतरे को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर स्थिति गंभीर है और डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने जलभराव और गंदगी वाले क्षेत्रों में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी अभियान चलाने की मांग की। यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता को घोषणाओं से ज्यादा जमीनी काम चाहिए। सरकार को सड़कों की मरम्मत, जल निकासी, सफाई, यातायात प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में लोगों को हर साल होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। कांग्रेस ने मांग की है कि दिल्ली सरकार जलभराव और टूटी सड़कों की समस्या को तत्काल दूर करने के साथ-साथ मच्छरजनित एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान शुरू करे।

## एक नजर

### नर्सिंग ऑफिसर डॉ. आशा ने यूरोप व अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियों पर फहराया तिरंगा

**गुरुग्राम।** भारत की बेटी 48 वर्षीय नर्सिंग ऑफिसर डॉ. आशा ने सिर्फ छह दिन में यूरोप और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटियों पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। डॉ. आशा के पति अजय सिंह हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। उनके दो बच्चों में से बेटी डॉक्टर और बेटा इंजीनियर है। नर्सिंग ऑफिसर डॉ. आशा ने 21 अगस्त 2026 को सुबह 09:07 बजे 5,642 मीटर ऊंची यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस और फिर 29 अगस्त 2026 को सुबह 05:31 बजे 5,895 मीटर ऊंची अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की उहुरू पीक फतह की। कैलेंडर के हिसाब से दोनों समिट में आठ दिन का अंतर रहा, जिसमें यात्रा और ट्रांजिट शामिल है, लेकिन प्रभावी क्लाइंबिंग सिर्फ छह दिन में की गई। दोनों चोटियों पर उन्होंने तिरंगे के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाया। डॉ. आशा ने 2017 में 39 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में तिब्बत की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वह भारत और विश्व की पहली नर्सिंग ऑफिसर के रूप में एवरेस्ट फतह करने का दावा करती हैं। पिछले 27 साल से राजस्थान सरकार में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर सेवारत डॉ. आशा अब सेवन समिट्स मिशन 2026-27 पर हैं, जिसके तहत सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना उनका लक्ष्य है। पर्वतारोहण के साथ-साथ डॉ. आशा 10, 25 और 50 मीटर एयर पिस्टल शूटर भी हैं। 2025 में उन्होंने मास्टर्स महिला वर्ग में 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते थे। रेवाड़ी के छोटे से गांव से शुरू हुई उनकी यात्रा युवाओं और महिलाओं के लिए संदेश है कि अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति से कोई भी शिखर असंभव नहीं।

### लाखों के फ्लैट, लेकिन घर के बाहर बदबू और सीवर का पानी

**साहिबाबाद।** ट्रांस हिंडन क्षेत्र में सीवर की समस्या विकट होती जा रही है। खासकर इंदिरापुरम और वैशाली में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि लोगों का घर से बाहर निकाला भी मुश्किल हो रहा है। वैशाली सेक्टर-3 और इंदिरापुरम के न्यायखंड में लोगों ने सीवर ओवरफ्लो की शिकायत की है। आरोप है कि इसके बाद भी नगर निगम के कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आते हैं। वार्ड-79 के तहत न्यायखंड-1 में मकान संख्या-738 जी के सामने सीवर का पानी अधिक मात्रा में भरा हुआ है इस बारे में स्थानीय निवासी प्रमोद तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की रात यहां के निवासियों के द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी होना है, जिसकी वजह से यहां निवासियों को आने-जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में गंदगी के कारण संक्रमण फैलने की भी आशंका बनी हुई है।

इसके अलावा वैशाली सेक्टर-3 में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि एक जगह सीवर ठीक करने पर दूसरी जगह खराब हो जाता है। ब्लॉक की एक गली में सीवर ओवरफ्लो होने से पानी भर गया है। निगम में इसकी शिकायत भी की गई है लेकिन पूरे दिन कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं आया। गली में जलभराव रहने से आवाजाही में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। गली में गंदा पानी घरों के सामने भरा पड़ा है। स्थानीय निवासी प्रिया ने बताया कि गली में पानी भरे होने से घरों से निकलना भी मुश्किल है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि सीवर की मेन लाइन साफ कराने की मांग निगम अधिकारियों से की गई है। जब तक मेन लाइन की सफाई नहीं कराई जाती है तब तक समस्या जस की तस बनी रहेगी। नगर निगम के अवर अभियंता सोमेंद्र तोमर ने बताया कि गली से जल निकासी कराई जाएगी।

### खालिस्तानी नेशनल आर्मी ने नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी

**गुरुग्राम।** नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल मिलते ही अधिकारी-कर्मचारी दफ्तर से बाहर दौड़े। सूचना पर पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे। पूरे परिसर को खाली कराकर सघन चेकिंग शुरू की गई। धमकी भरी ईमेल गुरुवार सुबह 11:38 बजे निगम की आधिकारिक आईडी पर आया। इसमें 1:11 बजे आईईडी ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। ईमेल खालिस्तानी नेशनल आर्मी के इंजीनियर गुरंख सिंह, रुकन शाहवाला, डॉ. गुरनिवेर सिंह और खान रजदा के नाम से भेजा गया है। ईमेल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाना बनाने, पांच और छह सितंबर को बठिंडा में और 13 सितंबर को क्रिकेट स्टेडियम में हमला करने की धमकी दी गई है।

साथ ही 700 किसानों का बदला भाजपा से लेने, अमृतसर के घरिंडा थाने, यूपी के डीजीपी यादव और उनके रिश्तेदारों पर हमले की बात कही गई है। ईमेल में लिखा है कि 13 सितंबर तक क्रिकेट खेलने के स्थान से बचें और किसी लावारिस आईफोन को हाथ न लगाएं, उससे धमाका हो सकता है। धमकी के बाद संबंधित राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। नगर निगम परिसर की हर मंजिल, पार्किंग और संदिग्ध जगहों की बारीकी से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस इसे शरारत या हॉक्स कॉल मान रही है, लेकिन कोई जोखिम नहीं ले रही। साइबर सेल ईमेल भेजने वाले को ट्रेस करने में जुटी है, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

# गुरुग्रामः डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को किया जाएगा और अधिक मजबूतः डॉ. सुमिता मिश्रा

**गुरुग्राम,एजेंसी।** हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) देश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मरीज और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के बीच ऐसी भरोसेमंद एवं निर्बाध व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। यह बात उन्होंने एबीडीएम मॉडल जिला एवं स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान कही। डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि एबीडीएम की सफलता तभी संभव है, जब सरकारी के साथ-साथ निजी स्वास्थ्य क्षेत्र भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सक्रिय रूप से अपनाएं। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा में सरकारी अस्पतालों और चिकित्सकों का एबीडीएम के तहत पंजीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों तथा स्वास्थ्य पेशेवरों की भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का मकसद केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर उनकी शंकाओं और व्यावहारिक समस्याओं को समझना तथा उनका समाधान करना है। उन्होंने कहा कि एबीडीएम आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनेगा। इसलिए स्वास्थ्य संस्थानों को समय रहते डिजिटल व्यवस्था के लिए तैयार होना चाहिए। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों, स्वास्थ्य संस्थानों, चिकित्सकों और तकनीकी भागीदारों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में अगले दो महीनों के दौरान जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों को एबीडीएम से जोड़ने, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने तथा क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।

प्रदेश में अब तक 1.92 करोड़ से अधिक आभा पहचान-पत्र बनाए जा चुके हैं, जो राज्य की अनुमानित आबादी का लगभग 65 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य कवरेज को और बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी एवं सार्थक उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की करीब 98 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री पर पंजीकृत हो चुकी हैं, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक लक्षित सरकारी चिकित्सकों का स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री पर पंजीकरण पूरा किया जा चुका है।

## टोल से राहत : जेवर के लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा टोल टैक्स

**ग्रेटर नोएडा।** यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण और संचालन के बाद से ही, लगभग विगत 14 वर्षों से जेवर क्षेत्र के स्थानीय निवासी एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क से राहत की मांग करते आ रहे थे। इस मांग को लेकर समय-समय पर क्षेत्र के अनेक किसान भाइयों, सामाजिक प्रतिनिधियों और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा भी लगातार प्रयास किए गए। स्थानीय नागरिकों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए अब जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली सुरक्षा समूह की कंपनी के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता की गई। क्षेत्रवासियों की दैनिक आवागमन संबंधी समस्याओं, किसानों के योगदान औ स्थानीय हितों को प्रमुखता से रखे जाने के बाद यह निर्णय हुआ है कि जेवर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित एवं आसपास के पात्र ग्रामों के स्थानीय नागरिकों को जेवर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से मुक्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र स्थानीय नागरिकों को अपने स्थानीय निवासी होने का प्रमाण, आधार कार्ड और वाहन की आरसी (ऋष्ट) की प्रति लेकर 17 सितंबर तक जेवर टोल प्लाजा के मैनेजर/निर्धारित कार्यालय में अपने वाहन का पंजीकरण कराना होगा।बताया कि आवश्यक सत्यापन एवं पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित व्यवस्था के अनुसार स्थानीय नागरिकों को टोल शुल्क मुक्त आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

## जब काम करते हुए समय का पता न चले, तो समझो करियर का फैसला सही है'

**ग्रेटर नोएडा।** मेरे ऊपर जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसे हम एहसास करने के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हमें समय का भी पता नहीं चलता है। दो मिनट के लिए सोचिए आज के पांच साल या 10 साल बाद आप अपने आपको कहां देखना चाहता हैं, इसी के बाद अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकोगे।

हालांकि इस दौरान सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। इससे आने वाले समय में कुछ सोचने की जरूरत न पड़े। जब काम करते हुए समय ही पता न चले तो समझ लेना कि आपने अपने करयिर में सही निर्णय लिया है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद पालना कोई गलत नहीं है। बस वह जिद सही काम के लिए होनी चाहिए। यह बातें भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बृहस्पतिवार को नॉलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय के 17वें ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कहीं। चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति की नींव है, और यह जरूरी है कि छात्र और फैकल्टी दोनों ही इनोवेशन, रिसर्च और अनुशासन को अपनाएं। भारत के युवाओं में अपार क्षमता है, और सही आदतों, सकारात्मकता और जीवनशैली के चुनाव से वे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाएं, खुद को चुनौती दें और समाज में सार्थक योगदान दें, क्योंकि भारत का भविष्य आपके हाथों में है। आज की युवा पीढ़ी पर हमारे देश को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है। युवा ही देश की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो आपकी जिद और जुनून ही दूसरे विकसित देशों की श्रेणी में ले जा सकती है। जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिंदगी में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद्दी बनना आवश्यक है। हर कदम पर डिमोटिवेट किया जाता है, लेकिन आपको अपने दिमाग में लक्ष्य को रखने की जरूरत है, डिमोटिवेट करने वाले लोगों को कभी भी सीरियस नहीं लेना है। आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा ने कहा कि व्यावहारिक ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि सैद्धांतिक शिक्षा। छात्रों को नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और साथ ही जिज्ञासा और इनोवेशन को अपनाना चाहिए।

## ग्रेटर नोएडा में अब कैंसिल नहीं होंगे प्लॉट, अलॉटीज को मिला 2028 तक का मौका

**अशोक कुमार, सद्भावना टुडे**

**ग्रेटर नोएडा।** ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड लेने के बाद तय समय में भवन निर्माण नहीं कराने वाले आवंटियों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने भवन निर्माण पूरा कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2028 कर दी है। हालांकि, इस राहत के लिए आवंटियों को प्रचलित दर के अनुसार विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री कराने के बाद भी निर्धारित समय सीमा में अपने भूखंड पर भवन निर्माण पूरा नहीं कराया है। ऐसे आवंटियों के सामने भूखंड का आवंटन निरस्त होने का खतरा था।

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि बोर्ड ने भवन निर्माण पूरा कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेने की समय सीमा 30 जून 2028 तक मान्य कर दी है। यह समय विस्तार वर्तमान में प्रचलित दर के अनुसार विलंब शुल्क जमा करने पर मिलेगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि आवंटी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लेता है तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू करने के लिए एनडीआरएफ की गाजियाबाद स्थित 8वीं वाहिनी के रीजनल रेस्पांस सेंटर को सेक्टर ओमीक्रान-1ए में 30 आवास निश्शुल्क आवंटित किए जाएंगे। एनडीआरएफ ने प्राधिकरण से भवन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। प्रस्ताव के अनुसार यहां तैनात कर्मी परिवार के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि आपदा और आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए टीम के रूप में तैनात रहेंगे। इन आवासों का उपयोग कैंप, परिसर और स्टाफ कार्यालय के रूप में किया जाएगा। टीम की तैनाती रोटेशन के आधार पर होगी। इससे प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक दुर्घटना, भवन गिरने और बाढ़ सहित अन्य आपात स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा को धूल मुक्त बनाने और प्रदूषण की रोकथाम के लिए सेंट्रल और ईस्ट जोन की सड़कों पर पांच वर्ष तक मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जाएगी। यह निर्णय सीएक्यूएम और आईआईटी रुड़की के सुझाव के आधार पर लिया गया है। प्राधिकरण मशीनरी उपलब्ध कराएगा, जबकि उसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। आईआईटी रुड़की के एस्टीमेट के आधार पर प्राधिकरण ने दोनों जोन के लिए ठेकेदार का चयन कर लिया है। सेंट्रल जोन में सेक्टर ईटा-1, डेल्टा-1, डेल्टा-2, डेल्टा-3, केपी-4, जीटा-1, ईटा-2 के साथ बेगमपुर, बोड़ाकी, मकौड़ा, मलकपुर, मुबारकपुर, पाली, साकीपुर और लखनावली सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। ईस्ट जोन में सेक्टर-36, 37, म्यू-1, ज्यू-1, ज्यू-2, ज्यू-3, चाई-5 के साथ अस्तौली, डाबरा, चुहड़पुर, घरबरा, घोड़ी-बछेड़ा, जुनपत, जुनैदपुर, घंघोला देवला, अजायबपुर, अटाई मुरादपुर, दाउदपुर, खेरली, लड़पुरा, लुक्सर, मायचा, कनारसी, कासना, खानपुर, पौवारी, सलेमपुर गुर्जर, बिरौंडी और बिरौंडा सहित अन्य गांवों की सड़कें शामिल हैं।

## 'मालखाना में नहीं, अपने घर में जन्मदिन मनाएंगे लड्डू गोपाल', जन्माष्टमी से एक पहले गाजियाबाद कोर्ट का फैसला

**गाजियाबाद,एजेंसी।** मंदिर से चोरी किए गए कान्हा की मूर्ति को बरामद कर पुलिस ने जन्माष्टमी से एक दिन पहले अदालत में पेश किया। चोर को भी अदालत के कठघरे में खड़ा किया गया। आमतौर पर बरामद सामान को मालखाना में रखा जाता है लेकिन जिस कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए अदालत का भी अवकाश था, वह कान्हा न्यायाधीश के सामने बरामदगी के रूप में थे। अदालत में अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि शुक्रवार को कान्हा का जन्मदिन हैं। कान्हा विधिक व्यक्ति हैं। अपने जन्मदिन पर वह मालखाने में कैसे रह सकते हैं।

अदालत ने दलीलों पर गौर करते हुए जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले ऐसा फैसला सुनाया कि कान्हा मालखाने में नहीं, बल्कि अपने मंदिर में जन्माष्टमी मनाएंगे। अदालत ने चोरी में बरामद लड्डू गोपाल और राधा रानी की मूर्तियों समेत पूजा का सामान मंदिर के पुजारी को सौंपने का आदेश दिया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से दो सितंबर की रात मंदिर से चोरी हुए लड्डू गोपाल व राधा रानी की मूर्ति, हनुमान की गदा समेत अन्य सामान को बरामद करने के बाद गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत में इस मामले की कहानी कुछ अलग थी। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत के सामने

कहा कि मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति को केवल कोई सामान मानकर लंबे समय तक मालखाने में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को मंदिर के पुजारी को सौंप दिया जाए। जब भी मुकदमे की जांच में जरूरत होगी, उन्हें अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा। अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि चार सितंबर को जन्माष्टमी है यानी कान्हा का जन्मदिन। मंदिर में इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लड्डू गोपाल की पूजा के बिना जन्माष्टमी का आयोजन पूरा नहीं हो सकता। पुजारी की ओर से यह भरोसा भी दिया गया कि जरूरत पड़ने पर मूर्तियां पुलिस या अदालत के सामने पेश कर दी जाएंगी। इसके लिए 50 हजार रुपये का निजी बंधपत्र और इतनी ही रकम का एक जमानती भी दाखिल किया गया। जन्माष्टमी से ठीक पहले मंदिर से कान्हा सहित अन्य मूर्ति चोरी हुई। पुलिस के लिए जन्माष्टमी से पहले चोरी का पर्दाफाश करना चुनौती था। इसके लिए पुलिस ने टीम गठित कर बड़ी संख्या सीसीटीवी कैमरे खंगाले। अखिरकार पुलिस जन्माष्टमी से पहले चोर को पकड़ने में सफल हो गई। बरामद मूर्तियों को पुलिस ने आम चोरी के सामान की तरह खुले में पेश नहीं किया। उन्हें सम्मान के साथ डिब्बे में रखकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने भी मामले की जरूरत और मूर्तियों के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुजारी की सुपुर्दगी में देने का आदेश दिया। आदेश में साफ कहा गया कि अगर आगे जांच के दौरान इनकी जरूरत पड़ती है तो पुजारी इन्हें विवेचक के सामने पेश करेंगे। यानी मुकदमे की जांच भी अपने रास्ते पर चलेगी और मंदिर में पूजा भी जारी रहेगी। पुजारी को केवल लड्डू गोपाल और राधा रानी की मूर्तियां ही नहीं, बल्कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला दूसरा सामान भी वापस दिया गया। इसमें हनुमान की पीतल की गदा, चरण पादुका, तीन पीतल की लुटिया, आरती की थाली, छह पीतल के दीपक, पांच ज्योत वाला एक दीपक, झूला और पीतल की घंटी समेत अन्य सामान शामिल है।

## शक्तिखंड में कार पर गिरा पेड़, करीब चार घंटे बंद रहा यातायात

**साहिबाबाद।** नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही बुधवार दोपहर को शक्तिखंड-3 और 4 में प्रवेश करने वाले मार्ग पर हुआ। दोपहर को एक पेड़ सड़क किनारे खड़ी कार पर गिर गया। हादसे के वक्त चालक कार में नहीं था, वरना जान पर बन सकती थी। आरोप है कि इस झुके पेड़ की शिकायत फोटो के साथ दो दिन पहले नगर निगम अधिकारियों से भी की गई थी। शक्तिखंड निवासी दीपा तोमर ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे शक्तिखंड-3 से 4 के रास्ते में कार पर एक पेड़ गिर गया था। इस दौरान राह से गुजर रहे दो बाइक सवार पेड़ के नीचे दबने से बाल-बाल बचे। लोगों ने तुरंत नगर निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना दी गई लेकिन इसके एक घंटे बाद टीम मौके से पेड़ हटाने पहुंची। लोगों ने उद्यान विभाग के सुपरवाइजर पंकज पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि सुपरवाइजर कई बार काल करने पर एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा और पेड़ को कटवाकर हटाया गया।

## गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा का सफर होगा आसान, शाहबेरी से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे तक बनेगी डबल डेकर रोड

**ग्रेटर नोएडा।** गाजियाबाद को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ने वाली शाहबेरी सड़क को डबल डेकर बनाने के प्रस्ताव को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वहीं, 130 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (एनएच-9) से जोड़ने की योजना को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। इन परियोजनाओं से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग शाहबेरी सड़क को डबल डेकर बनाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के डबल डेकर बनने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

बोर्ड की मंजूरी के बाद सड़क को विकसित करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच आवागमन को बेहतर बनाना और इस क्षेत्र में यातायात को अधिक सुचारु करना है। ग्रेटर नोएडा में 130 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने की दिशा में भी कवायद तेज हो गई है। इस संबंध में प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिस पर सहमति बन गई है। अब नोएडा और यमुना प्राधिकरण की सहमति लेकर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने के लिए एनएचएआई को जिम्मेदारी सौंपी थी। सर्वेक्षण में दो वैकल्पिक मार्ग सामने आए। पहले विकल्प में एक मूर्ति से नाले तक डबल डेकर सड़क प्रस्तावित की गई थी, जबकि दूसरे विकल्प में शाहबेरी से नाले के साथ लिंक रोड जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। परियोजना के लिए बनी समिति ने पहले चरण में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से एक मूर्ति तक डबल डेकर सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इस चरण पर 756.01 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

## पहले तो कोरोना काल में घट गई ट्रेनें, अब आठ लोकल का संचालन भी बंद

**पलवल।** कोरोना काल के बाद से ही पलवल के दैनिक रेल यात्री ट्रेनों के संचालन की कमी से जूझ रहे थे। अब फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते पलवल-दिल्ली रेलमार्ग पर आठ लोकल ट्रेनों का संचालन स्थगित होने से दैनिक यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। रेलवे ने एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक आठ ईएमयू एवं लोकल ट्रेनों को रद्द किया है। इससे दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद की ओर रोजाना नौकरी, पढ़ाई और अन्य कामों के लिए जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। रद्द की गई ट्रेनों में 64015 पलवल-शकूरबस्ती, 64057 पलवल-गाजियाबाद, 64012 शकूरबस्ती-पलवल, 64013 पलवल-शकूरबस्ती, 64052 गाजियाबाद-पलवल, 64078 नई दिल्ली-पलवल, 64908 शकूरबस्ती-बल्लभगढ़ और 64071 बल्लभगढ़-शकूरबस्ती शामिल हैं। पलवल से बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग और विद्यार्थी प्रतिदिन दिल्ली, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन करते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन है। यात्रियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद कई यात्री ट्रेनें पहले की तरह नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यहां दैनिक रेल यात्री एसोशिएशन महासचिव प्रकाश चंद मंगला ने गुरूवार को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यूनियन पिछले पांच-छह वर्षों से रद्द की गई ट्रेनों का पुन: संचालन तथा पलवल से गुजरने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों के ठहराव की मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए वे डीआरएम से लेकर रेल मंत्री तक कई बार मिलकर ज्ञापन भी दे चुके हैं उनकी मांग और कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में अब निर्माण कार्य के कारण कुछ और ट्रेनों का संचालन बंद होने से मुश्किल बढ़ गई है। यात्रियों के अनुसार, लोकल ट्रेन का पास होने के बावजूद ट्रेन रद्द होने पर बस, मेट्रो या अन्य साधनों का किराया देना पड़ रहा है। इससे रोजाना यात्रा का खर्च बढ़ गया है। यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि निर्माण कार्य के दौरान प्रभावित रूट पर वैकल्पिक ट्रेनें या परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। रेलवे मुख्यालय के आदेश के अनुसार फरीदाबाद स्टेशन पर विकास कार्य रात के समय कराया जाएगा।

## पुलिस टीम पर हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

**नूंह,एजेंसी।** नूंह जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने पुलिस टीम पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अवैध हथियार रखने तथा हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने गुरुवार को दोषी लियाकत और उस्मान को अधिकतम पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार मामला 11 अगस्त 2020 का है। दोनों आरोपियों ने साझा मंशा के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा डाली तथा उनके साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुंचाईं। इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। अदालत ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में दोषी माना। मामले की जांच के दौरान आरोपी उस्मान के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद हुए थे। वहीं लियाकत के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया था। दोनों आरोपियों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं

मिला था। अदालत ने लियाकत को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, आरोपी उस्मान को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ आर्म्स एक्ट की अतिरिक्त धारा में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस्मान पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

# सिंधु जल विवाद केस जीतकर भी दुखी पाक

**पुष्परंजन**

नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन) द्वारा सिंधु जल विवाद के एकतरफा फैसले पर पाकिस्तान बल्ले-बल्ले, शाबाश-शाबाश करने लगा है। हेग स्थित 'पीसीए' ने सोमवार को फैसला सुनाया है कि भारत एकतरफा तरीके से सिंधु जल संधि को सस्पेंड नहीं कर सकता। कोर्ट ने नई दिल्ली की उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया है, जिनका इस्तेमाल उसने छह दशक पुराने जल-बंटवारे के समझौते को अप्रैल, 2025 से 'स्थगित' रखने को सही ठहराने के लिए किया था। सोमवार को सुनाए गए सर्वसम्मत फैसले में पांच सदस्यीय कोर्ट ने पाया कि संधि 'पूरी तरह से लागू है' और भारत को इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। इसमें पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। पहलगाम हमला 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के बैसारन घास के मैदानों में हुआ था, जिसमें पाक-पोषित बंदूकधारियों ने बर्बरता से 26 लोगों की जान ले ली थी। बंदूकधारियों ने गोली दागने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा था। इस नरसंहार के बाद, भारत ने कहा था कि वह संधि को तब तक सस्पेंड रखेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को 'विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय' रूप से खत्म नहीं कर देता। इस्लामाबाद इन आरोपों से इनकार करता है कि वह हमले के पीछे था। लेकिन माजी में दी उसकी धमकियों से कोई मानने को तैयार नहीं कि पहलगाम कांड में उसका हाथ नहीं रहा है। बहरहाल, पाकिस्तान द्वारा हेग में लाए गए सिंधु जल संधि मामले में भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में जलविद्युत परियोजनाएं बनवाने वाला चीन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। माजी में चीन ने भी परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन के एक ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया था, जो दक्षिण चीन सागर के विवाद पर फिलीपींस के पक्ष में आया था। ऐसा नहीं कि नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भारत ने कोई केस लड़ा ही नहीं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत अब तक 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का हिस्सा रहा है।

मगर सवाल है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यदि पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुना भी दिया, तो उसे लागू कैसे करवाएगा? भारत ने कुछ ही घंटों में इस फैसले को खारिज कर दिया था। यह दिलचस्प है कि 1 सितंबर, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक ही मंच पर मौजूद रहे, लेकिन दोनों में न बात हुई, न इस विषय पर कोई चर्चा। हालांकि, इस्लामाबाद में रहने वाले हाइड्रोलॉजी और जल संसाधन विशेषज्ञ हसन अब्बास इस बात से सहमत नहीं थे कि समझौते के टूटने से फिलहाल पाकिस्तान के लिए कोई तत्काल खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा खतरा है। पश्चिमी नदियां भौगोलिक स्थिति की वजह से सुरक्षित हैं, न कि मुख्य रूप से संधि की वजह से। हसन अब्बास ने बताया कि चिनाब नदी पर भारत की स्टोरेज क्षमता लगभग 1 मिलियन एकड़-फीट (405,000 हेक्टेयर-फीट) है, जो पाकिस्तान की मौसमी सिंचाई की जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है। उन्होंने कहा, 'अगर वे कहते हैं कि वे पानी नहीं बहने देंगे, तो वे खुद ही बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि भारत के बांध रन-ऑफ-रिवर हाइड्रोपावर प्लांट हैं, जिनमें पानी जमा करने की जगह बहुत कम होती है।' अब्बास ने कहा, 'एक बार जब उनके बांध भर जाते हैं, तो उनके पास पानी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।' लेकिन हाइड्रोलॉजी और जल संसाधन विशेषज्ञ हसन अब्बास ने पाकिस्तान के अपने जल प्रबंधन की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लामाबाद का नए बड़े बांधों पर जोर देना सस्ते समाधानों को नजरअंदाज करता है। जल विशेषज्ञ अब्बास ने कहा कि सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर नए जलाशयों की तुलना में कहीं ज्यादा पानी बचाया जा सकता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी की मुख्य धारा पर वर्तमान में कई प्रमुख मेगा जलविद्युत और बांध परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें दासू और दियामेर-भाशा जैसी बड़ी परियोजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। दासू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिंधु नदी पर बन रहा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। उसी तरह दियामेर-भाशा बांध गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर सिंधु नदी पर रोलर-कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से बन रहा 272 मीटर ऊंचा विशाल बांध है। इसके अलावा सिंधु नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों पर अन्य छोटी-बड़ी जलविद्युत एवं सिंचाई परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। पाकिस्तान के पास पानी का टोटा है, लेकिन जलविद्युत परियोजनाएं मालूम नहीं किसके भरोसे पूरी की जा रही हैं? सिंधु जल संधि से हटने के भारत के एकतरफा फैसले के बाद से पाकिस्तानी अधिकारियों और मिलिट्री लीडरशिप ने इस विवाद को अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर बताना शुरू कर दिया है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बोल चुके हैं कि यह विवाद कोई तकनीकी विवाद नहीं है... यह कागजी कार्रवाई, हाइड्रोलॉजी या प्रशासनिक देरी का मामला भी नहीं है। यह 'पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल' है।

बात पाकिस्तान वालों को देर से समझ में आई कि भारत ने उसके विरुद्ध अबूझ 'वाटर बम' का इस्तेमाल किया है। 'इब्तदा-ए-इश्क है, रोता है क्या/ आगे-आगे देखिए, होता है क्या।' लद्दाख से ऐसी खबर आई है, जिसका यदि पालन हो गया, तो पाकिस्तान वाकई बूंद-बूंद पानी के लिए तरसेगा। लद्दाख प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, सिंधु नदी के सीने पर एक साथ 36 डैम्स का जाल बिछाने का। वो पानी, जो अब तक खैरात में सरहद पार जा रहा था। वह पानी अब भारत की बंजर जमीन को सोना बनाने वाला है। मात्र 56 करोड़ के बजट में लद्दाख ने वो दांव खेल दिया है, जो पाकिस्तान के रणनीतिकारों ने सोचा भी नहीं था। जो प्रस्ताव लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जल शक्ति मंत्रालय को भेजा है, वह पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ाने वाला कदम है। पहला प्लान है लेह में सात रॉक डैम्स। यह बनेंगे इंडस रिवर के ऊपर। दूसरा प्लान है, कारगिल में 29 आरसीसी डैम्स। यह बनेंगे सुरू नदी पर, जो सिंधु की सबसे ताकतवर ट्रिब्यूटरीज में से एक है। दिल्ली, कब और कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को स्वीकार और साकार करता है, उसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन, नई दिल्ली को इसमें देर नहीं करनी चाहिए।

इस वर्ष 4 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण की 5253वीं जन्माष्टमी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों, भजन-कीर्तन और मध्यरात्रि में भगवान के जन्मोत्सव के साथ यह पर्व भारतीय सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जन्माष्टमी के दिन देशभर में मंदिरों को सजाया जाता है, लोग रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे शंख और घंटों की ध्वनि के जरिये भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बाल्याकाल में अनेकों लीलाएं की, जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसी ही अनेक लीलाओं का मंचन किया जाता है। सही मायनों में श्रीकृष्ण हमारे इतिहास के अभिन्न अंग हैं, जिनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व जितना मोहक था, उतना ही रहस्यमयी भी और उतनी ही अनोखी थी उनकी लीलाएं। बाल्यावस्था से लेकर जीवनपर्यन्त लीलाएं करते रहे श्रीकृष्ण में कभी भगवान के दर्शन होते हैं तो कभी वे एक साधारण मानव सरीखे प्रतीत होते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि मानव के रूप में भी श्रीकृष्ण उतना ही आकर्षित करते हैं, जितना कि भगवान के रूप में। उनका एक-एक कार्य मन में गहरा स्थान बना जाता है। उनके आदर्श, उनके जीवन की विद्वत्ता, वीरता, कूटनीति, योगी सदृश उज्ज्वल , निर्मल एवं प्रेरणादायक पक्ष, सब हमारे लिए अनुकरणीय हैं। श्रीकृष्ण को प्रेम एवं मित्रता के अनुपम प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है।

# जीवंत है श्रीकृष्ण का विराट व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन

**योगेश कुमार गोयल**

**(जन्माष्टमी विशेष)**

भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी का पावन पर्व सम्पूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनमानस के नायक, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन-दर्शन में श्रीकृष्ण के विराट व्यक्तित्व और उनके लोक कल्याणकारी संदेशों का स्मरण कराने वाला पर्व है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के संयोग में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण हुआ था। अत्याचारी कंस के आतंक से त्रस्त मथुरा में श्रीकृष्ण का जन्म अन्याय और अधर्म के विरुद्ध धर्म, सत्य और न्याय की विजय की आशा का प्रतीक बना। पौराणिक मान्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के पूर्णावतार माने जाते हैं और उनके व्यक्तित्व में बाल-सुलभ चंचलता, अद्भुत करुणा, अनुपम प्रेम, असाधारण पराक्रम, दूरदर्शी कूटनीति तथा गहन आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने भगवद्गीता के माध्यम से कर्म, धर्म और कर्तव्य का ऐसा कालजयी संदेश दिया, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। इस वर्ष 4 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण की 5253वीं जन्माष्टमी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों, भजन-कीर्तन और मध्यरात्रि में भगवान के जन्मोत्सव के साथ यह पर्व भारतीय सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जन्माष्टमी के दिन देशभर में मंदिरों को सजाया जाता है, लोग रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे शंख और घंटों की ध्वनि के जरिये भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बाल्याकाल में अनेकों लीलाएं की, जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसी ही अनेक लीलाओं का मंचन किया जाता है। सही मायनों में श्रीकृष्ण हमारे इतिहास के अभिन्न अंग हैं, जिनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व जितना मोहक था, उतना ही रहस्यमयी भी और उतनी ही अनोखी थी उनकी लीलाएं। बाल्यावस्था से लेकर जीवनपर्यन्त लीलाएं करते रहे श्रीकृष्ण में कभी भगवान के दर्शन होते हैं तो कभी वे एक साधारण मानव सरीखे प्रतीत होते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि मानव के रूप में भी श्रीकृष्ण उतना ही आकर्षित करते हैं, जितना कि भगवान के रूप में। उनका एक-एक कार्य मन में गहरा स्थान बना जाता है। उनके आदर्श, उनके जीवन की विद्वत्ता, वीरता, कूटनीति, योगी सदृश उज्ज्वल , निर्मल एवं प्रेरणादायक पक्ष, सब हमारे लिए अनुकरणीय हैं। श्रीकृष्ण को प्रेम एवं मित्रता के अनुपम प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। बचपन के निर्धन मित्र सुदामा को उन्होंने अपने राज्य में जो मान-सम्मान दिया, वह मित्रता का अनुकरणीय उदाहरण बना।

श्रीकृष्ण की लीलाओं को समझना जहां पहुंचे हुए ऋषि-मुनियों और बड़े-बड़े विद्वानों के बूते से भी बाहर था, वहीं अनपढ़, गंवार माने जाते रहे निरक्षर और भोले-भाले ग्वाले और गोपियां उनका सानिध्य पाते हुए उनकी दिव्यता का सुख पाते रहे। उन्हें कन्हैया कहें या कृष्ण, पीताम्बर कहें या वासुदेव या फिर देवकीनंदन अथवा यशोदानंदन, वास्तव में श्रीकृष्ण का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे महाभारत काल के ऐसे आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दृष्टा रहे, जिन्होंने धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दुर्जनों का संहार किया। वे शांति, प्रेम एवं करूणा के साकार रूप थे। महाभारत युद्ध के समय शांति के सभी प्रयास विफल होने पर उन्होंने संशयग्रस्त धनुर्धारी अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देकर कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर किया और अन्याय की सत्ता को उखाड़ने के लिए अपने ही कौरव भाइयों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें अपने कर्मों का पालन करने के लिए गीता का उपदेश दिया। युद्ध के समय वे हर पल धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म करने वालों के खिलाफ खड़े नजर आए, इसीलिए उन्हें अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। गीता में उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा था:-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम।।

अर्थात् हे भारत! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं अर्थात् साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक श्रीकृष्ण की अनेक लीलाएं विख्यात हैं। श्रीकृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी का आव्हान किया था, जिसके बाद हनुमान ने बलराम की वाटिका में जाकर बलराम से युद्ध किया और उनका घमंड चूर-चूर कर दिया था। श्रीकृष्ण ने नररकासुर नामक असुर के बंदीगृह से 16100 बंदी महिलाओं को मुक्त कराया था, जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाने पर उन महिलाओं ने श्रीकृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाई और तब श्रीकृष्ण ने उन सभी महिलाओं को अपनी रानी होने का दर्जा देकर उन्हें सम्मान दिया था।

अपने एक उपदेश में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा था:-

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।

अर्थात् साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूं। श्रीकृष्ण का स्वरूप कितना दिव्य था, इसकी अनुभूति इसी से हो जाती है कि एक ओर जहां अपने स्तनों पर विष लेप कर मां का रूप धारण कर दूध पिलाने आई राक्षसी पूतना का दूध पीकर श्रीकृष्ण उसे मां का सम्मान देते हैं तो दूसरी ओर उसकी दुष्टता के लिए उसका वध भी करते हैं। श्रीकृष्ण ने लंबे समय तक द्वारका पर शासन किया, इसीलिए उन्हें द्वारकाधीश नाम से भी जाना जाता है। 36 वर्ष तक द्वारका पर शासन करने के बाद वे परम धाम को प्राप्त हुए थे। पाप-पुण्य, नैतिक-अनैतिक, सत्य-असत्य से परे पूर्ण पुरुष की अवधारणा को साकार करते श्रीकृष्ण भारतीय परम्परा के ऐसे प्रतीक हैं, जो जीवन का प्रतिबिम्ब हैं और सम्पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनका चित्र जनमानस के हृदय पटल पर एक कुशल नेतृत्वकर्ता, योद्धा, गृहस्थी, सारथी, योगीराज, देवता इत्यादि विविध रूपों में अंकित है। श्रीकृष्ण बंधन भी हैं और मुक्ति भी, एक ओर जहां वे अपने भक्तों को अपने आकर्षण में बांधते हैं तो उन्हीं भक्तों को मोह-माया के बंधन से मुक्त भी करते हैं।

## विचार

# मौलिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में न्यायिक पहल

**डॉ. जगदीप सिंह**

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जो पूरे देश के युवाओं के लिए राहतकारी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जंतर-मंतर और देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि सद्भावना से आए युवाओं का भविष्य आपराधिक मामलों की छाया में नहीं रहना चाहिए। यह निर्णय सिर्फ कानूनी राहत नहीं। यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्रों के अधिकारों की पुष्टि है। ये प्रदर्शन नीट-यूजी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुए थे। दिल्ली पुलिस ने अकेले इस अवधि में 13 एफआईआर दर्ज की थीं। हजारों छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आए और जंतर-मंतर पर जमा हुए। प्रदर्शन जल्द ही कई राज्यों में फैल गया। केंद्र सरकार के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा असम आदि की सरकारों ने अदालत में अर्जी दायर कर इन मामलों को रद्द करने की अनुमति मांगी। अदालत ने न सिर्फ इन अर्जियों को स्वीकार किया, बल्कि पूरे देश पर अपना आदेश लागू कर दिया। किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उसी घटना से जुड़ी एफआईआर अगर अभी तक सामने नहीं आई, तो उसे भी बंद माना जाएगा। कोई नई एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकेगी। ये निर्देश पूरे भारत पर लागू होते हैं। इससे साफ होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी एक शहर या घटना तक सीमित नहीं, यह पूरे देश के नागरिकों का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) हर नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। इसमें शांतिपूर्ण सभा और विरोध का अधिकार भी शामिल है। जंतर-मंतर पर छात्र इसलिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि वे परीक्षा व्यवस्था की खामियों और अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर आवाज उठाना चाहते थे। प्रदर्शन लोकतंत्र का स्वस्थ लक्षण है। जब प्रशासन इस आवाज को दबाने के लिए एफआईआर का सहारा लेता है, तो संविधान का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक यही कमजोरी दूर की। अदालत ने कहा कि युवा प्रदर्शनकारी, जो सद्भावना से आए थे, उनके खिलाफ मामले आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र में नागरिकों को बिना भय के अपनी बात कहने, नीतियों पर सवाल उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए जाएं, तो युवा पीढ़ी चुप हो जाएगी।

निस्संदेह, अनु.-19 की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संविधान स्वयं अनुच्छेद-19(2) में उचित प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। हिंसा, तोड़फोड़ या गंभीर अपराध करने वालों को राहत नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने ठीक यही संतुलन बनाया। दिल्ली पुलिस को उन लगभग 2,873 व्यक्तियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई, जिनके गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हैं। हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मामलों वाले लोग इस राहत के दायरे से बाहर हैं। यह फैसला दिखाता है कि अदालत स्वतंत्रता और व्यवस्था दोनों की रक्षा कर रही है। शांतिपूर्ण आवाज को जगह दी गई, लेकिन अपराध को बर्दाश्त नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया है और मिसाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा प्रणाली, रोजगार और शिक्षा की गुणवत्ता उनके जीवन को तय करती है। जब वे इन मुद्दों पर बोलते हैं, तो उन्हें आपराधिक रंग में रंगना गलत है। एफआईआर का बोझ उनके कैरियर, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कई छात्र नौकरी, उच्च शिक्षा या विदेश जाने की तैयारी में होते हैं। आपराधिक केस उनके सपनों पर पानी फेर सकता है। अदालत ने केंद्र सरकार के उन आश्वासनों को भी नोट किया, जिसमें मुआवजे और मामलों को आगे न बढ़ाने की बात कही गई थी। नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को तीन महीने के अंदर मुआवजा देने का आश्वासन भी रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज मिलकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार इसलिए जरूरी है कि सत्ता हमेशा सही नहीं होती। परीक्षा व्यवस्था में खामियां, पेपर लीक होना या पारदर्शिता की कमी-ये मुद्दे सिर्फ छात्रों के नहीं, पूरे समाज के हैं। जब छात्र इन मुद्दों को उठाते हैं, तो समाज में चेतना जगाते हैं। यह फैसला लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है।

## एक नजर

### बाल कृष्ण-राधा के रूप में सजे बच्चों ने मोहा मन, श्रीकृष्ण बाल मेला में दिखी प्रतिभा और संस्कार की झलक

**सीवान,एजेंसी।** शहर के भगवान पैलेस में गुरुवार को सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट की ओर से आयोजित श्रीकृष्ण बाल मेला 2026 में बाल कृष्ण और राधा रानी के रूप में सजे सैकड़ों बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। नृत्य, गायन और विभिन्न खेलों के साथ भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय पाण्डेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि डॉ. रूपेश कुमार सोनी, डॉ. गणेश दत्त पाठक, डॉ. शम्सुद्दीन आजाद, डॉ. आरती आलोक वर्मा, पत्रकार अरविंद पाठक, राजा भैया और आशीष कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेले में बच्चों ने बाल कृष्ण और राधा रानी का रूप धारण कर अपनी आकर्षक वेशभूषा से सभी का ध्यान खींचा। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन स्थल पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को ट्रस्ट की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि संजय पाण्डेय ने कहा कि सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट, टीम अनमोल द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। इस तरह के आयोजनों से बच्चों की प्रतिभा को मंच मिलता है और उनमें भारतीय संस्कृति व संस्कारों के प्रति जुड़ाव बढ़ता है। बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों से जोड़ना पुनीत कार्य है। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष अनमोल कुमार ने कहा कि श्रीकृष्ण बाल मेला जैसे आयोजन बच्चों में भारतीय संस्कृति और संस्कारों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ट्रस्ट का उद्देश्य सीवान में बेहतर समाज के निर्माण के साथ संस्कारवान और प्रतिभाशाली पीढ़ी तैयार करना है। मौके पर ट्रस्ट के सचिव अभिमन्यु कुमार, कार्यकारिणी अध्यक्ष चंदन कुमार, कोषाध्यक्ष सूरज कुमार, प्रवक्ता नीतीश कुमार, आशीष रंजन, कंचन, प्रीतम, अंकित कुमार सहित ट्रस्ट के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे।

### सत्यदेव उच्च विद्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण

**सुपौल।** जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने गुरुवार को पिपरा स्थित सत्यदेव उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों एवं शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक ने बताया कि कुछ विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, उनके अभिभावकों को विधिवत सूचना अथवा नोटिस देकर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। डीएम ने विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम से लगातार जोड़कर रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों के लेसन प्लान की समीक्षा की और नियमित रूप से पाठ योजना तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। प्रधानाध्यापक को प्रत्येक कक्षा में विषयवार माइक्रोप्लान प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों को पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का नियमित अभ्यास कराने तथा प्रत्येक कक्षा में पूर्व में पढ़ाए गए पाठ का संक्षिप्त पुनरावलोकन कराने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक शिक्षक के पास संबंधित सिलेबस, पाठ योजना एवं आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध रहे। जिला पदाधिकारी ने शिक्षकों से शिक्षण कार्य को और अधिक रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों की मजबूत शैक्षणिक नींव तैयार करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से ही विद्यार्थी शैक्षिक रूप से सशक्त होकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। उन्होंने सभी शिक्षकों से अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करने का आग्रह किया। निरीक्षण के दौरान डीपीओ माध्यमिक शिक्षा एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पिपरा उपस्थित रहे।

### संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत विकास शिविर का निरीक्षण

**सुपौल।** श्री गुरु संत रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य स्तर पर चलाए जा रहे श्री गुरु संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को विभिन्न प्रखंडों में विकास शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार ने दिनापट्टी पंचायत में आयोजित श्री संत रविदास विकास शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने शिविर में मौजूद पदाधिकारियों एवं कर्मियों से बातचीत कर शिविर में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि शिविर में सबसे अधिक आवेदन परिवार के अलग होने के कारण पूर्व के राशन कार्ड से अलग नया राशन कार्ड बनवाने से संबंधित प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दिव्यांगता से संबंधित सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए भी लोगों ने आवेदन दिए। उप विकास आयुक्त ने शिविर में मौजूद विकास मित्र एवं शिविर प्रभारी को सभी प्राप्त आवेदनों का विधिवत परीक्षण करते हुए नियमानुसार त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि अधिकतर आवेदनों का निष्पादन दो से तीन दिनों के अंदर कर दिया जाता है तथा पात्र आवेदकों को आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। डीडीसी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विकास शिविर के आयोजन से पहले क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करना है। इसके लिए प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिविर के दौरान स्थानीय मुखिया सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

# बेंगलुरु पहुंचे सम्राट चौधरी और संजय सरावगी, 'बिहार महोत्सव' में होंगे शामिल

**पटना,एजेंसी।** बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी गुरुवार को बेंगलुरु पहुंचे। दोनों यहां 'बिहार महोत्सव' कार्यक्रम में शामिल होंगे। हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में मौजूद बिहारवासियों ने मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बिहार से दूर रह रहे प्रवासी बिहारियों ने अपने नेताओं के प्रति स्नेह और अपनत्व व्यक्त किया। बेंगलुरु पहुंचने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री गौशाला पहुंचे और वहां गौ सेवा की। उन्होंने गायों को फल खिलाए। हवाई अड्डे पर हुए स्वागत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि बेंगलुरु में बिहार के लोगों से मिले स्नेह, सम्मान और अपनत्व से वह अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से दूर रहकर भी अपनी माटी, संस्कृति और संस्कारों से जुड़े लोगों का यह स्नेह हृदय को छू गया। बिहार के लोग देश के जिस भी हिस्से में रहते हैं, अपनी मेहनत, प्रतिभा और संस्कारों के माध्यम से बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं।

सरावगी ने कहा कि बेंगलुरु दौरे के दौरान वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ 'बिहार महोत्सव-2026' के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के माध्यम से बिहार की समृद्ध लोक परंपराओं, कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। लोकगीत, लोकनृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और लोक परंपराएं बिहार की गौरवशाली विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं।' बिहार महोत्सव-2026' के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को बिहार की सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित होने का अवसर मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह महोत्सव बिहार के गौरव, उसकी विरासत और सांस्कृतिक विविधता को देश के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। साथ ही, यह प्रवासी बिहारियों को अपनी जड़ों, अपनी माटी और अपनी संस्कृति से जोड़ने का भी सशक्त अवसर है।

### बिहार में खेल का एक नया वातावरण तैयार हो रहा है और हमारे स्कूली बच्चे इसके महत्वपूर्ण भागीदार होंगे : श्रेयसी सिंह

**पटना।** बिहार सरकार के खेल विभाग की पहल पर मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के अंतर्गत कक्षा 06 से 12 तक के चयनित छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में राज्य के प्रमुख खेल परिसरों एवं स्टेडियमों को शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बिहार में विकसित हो रहे आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं खेल गतिविधियों से परिचित कराना तथा उनमें खेलों के प्रति रुचि एवं जागरूकता को बढ़ावा देना है।

इस क्रम में विद्यार्थियों को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना, राज्य खेल एकेडमी, राजगीर तथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर का भ्रमण कराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को राज्य में खेल क्षेत्र में हो रहे विकास को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में खेलों के विकास एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना में प्रमुख खेल परिसरों को शामिल किया जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे केवल किताबों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से भी राज्य में विकसित हो रही आधुनिक खेल सुविधाओं को देखें और समझें। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना में प्रमुख खेल परिसरों को शामिल करना हमारे युवाओं को खेलों से जोड़ने और उनमें खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बिहार में खेल का एक नया वातावरण तैयार हो रहा है और हमारे स्कूली बच्चे इसके महत्वपूर्ण भागीदार होंगे। खेल विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि विद्यार्थियों को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा राजगीर स्थित राज्य खेल एकेडमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसी सुविधाओं का भ्रमण कराने से उन्हें राज्य के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण व्यवस्था को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। हमारा प्रयास है कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों में खेल के प्रति जिज्ञासा, आत्मविश्वास और भविष्य में खेल को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करेगी। यह पहल विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने, खेल प्रतिभाओं को पहचानने एवं बिहार में सुदृढ़ हो रही खेल संस्कृति को विद्यालय स्तर तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

### सीमावर्ती युवाओं के लिए 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू

**सुपौल,एजेंसी।** सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), बीरपुर की ओर से 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 3 सितंबर 2026 को कमांडेंट गौरव सिंह के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के चयनित युवाओं को कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान के साथ डिजिटल तकनीक, इंटरनेट तथा कंप्यूटर के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण आईटीआई, बीरपुर के कुशल एवं अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमांडेंट गौरव सिंह ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में कंप्यूटर एवं तकनीकी ज्ञान प्रत्येक युवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युवाओं को प्रशिक्षण में नियमित रूप से उपस्थित होकर पूरी लगन और मेहनत के साथ सीखना चाहिए तथा प्रशिक्षण के दौरान हासिल ज्ञान का उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षकों से भी प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। कौशल विकास से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर हासिल करने के लिए तैयार होते हैं। कमांडेंट ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं है। वहां के युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 45वीं वाहिनी एसएसबी, बीरपुर की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा दायित्वों के निर्वहन के साथ नागरिक कल्याण, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक उत्थान से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सीमावर्ती लोगों के साथ एसएसबी के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

### मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना मेट्रो की रफ्तार बढ़ाने पर दिया जोर, समयबद्ध पूर्णता का दिया निर्देश

**पटना,एजेंसी।** नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गुरुवार को पटना मेट्रो डिपो का निरीक्षण कर पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने तथा निर्माण कार्यों में अपेक्षित गति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक से पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना मेट्रो डिपो परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए परियोजना परिसर में स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विज़न बिहार के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और बेहतर कनेक्टिविटी से युक्त विकसित शहरों के रूप में स्थापित करना है। पटना मेट्रो इसी विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव-सह-प्रबंध निदेशक, पीएमआरसीएल, संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी ने पटना मेट्रो परियोजना के विभिन्न कॉरिडोर एवं सेक्शन में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रमुख माइलस्टोन, निर्धारित समय-सीमा तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान विभिन्न कॉरिडोर एवं सेक्शन में निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा आगामी चरणों की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके त्वरित समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा

निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप सभी लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर उत्पन्न होने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए।

मंत्री नीतीश मिश्रा ने निर्देश दिया कि पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जल्द से जल्द आम लोगों को बेहतर, सुगम एवं सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और कनेक्टिविटी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान आमजन को बिल्कुल असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रभावी व्यवस्था करने, वैकल्पिक मार्गों एवं आवश्यक डायवर्जन की समुचित जानकारी उपलब्ध कराने तथा सड़क पर आवागमन को सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना से जुड़ी सभी एजेंसियों, अधिकारियों एवं संवेदकों के बीच बेहतर एवं प्रभावी समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समयबद्धता के साथ-साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने परियोजना के प्रत्येक चरण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

### महावीरी मेले को लेकर शहर में फ्लैग मार्च, डीएम-एसपी ने पैदल घूमकर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

**सीवान।** महावीरी अखाड़े और मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार की देर रात निकलने वाले महावीरी अखाड़े के जुलूस और रविवार की सुबह से आयोजित होने वाले मेले को लेकर गुरुवार को शहर में प्रशासन और पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया।

जिलाधिकारी विकास कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में निकले फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल हुए।समाहरणालय परिसर से निकला फ्लैग मार्च जेपी चौक, शास्त्री नगर, नया किला, पुरानी किला, स्टेशन रोड, शहीद मार्ग, बबुनिया रोड, बड़हरिया स्टैंड समेत शहर के प्रमुख मार्गों और मोहल्लों से गुजरा। जुलूस के दौरान पुलिस के सायरन और जवानों की कदमताल से शहर का माहौल पूरी तरह पुलिस छावनी जैसा नजर आया। फ्लैग मार्च को देखने के लिए सड़क किनारे और घरों की छतों पर लोगों की भीड़ जुट गयी। महावीरी अखाड़े के निर्धारित रूट से जब डीएम, एसपी और पुलिस के जवान गुजरे तो कई स्थानों पर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर फ्लैग मार्च देखने लगे। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों और जुलूस मार्ग का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। फ्लैग मार्च के माध्यम से प्रशासन ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देने का प्रयास किया। प्रशासन ने महावीरी मेले के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए हैं।

अखाड़े के मेले में ऑर्केस्ट्रा के आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी।

पूजा समितियों को डीजे बजाने और अश्लील गीतों का प्रसारण करने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने अखाड़ा समितियों और आम लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की है। शुक्रवार की देर रात से महावीरी अखाड़े का जुलूस निकाला जाएगा, जबकि रविवार की सुबह से विभिन्न स्थानों पर महावीरी मेले का आयोजन होगा। पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी की व्यवस्था की गयी है। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ सदर अजय कुमार सिंह, नगर थाना इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, सराय थानाध्यक्ष विकास कुमार बिट्टू, महादेवा थानाध्यक्ष विनीत विनायक, मुफस्सिल थानाध्यक्ष उपेंद्र सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल रहे।

### गंगा नदी के उच्चतम जलस्तर पार करने की संभावना को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट, निचले इलाकों में विशेष सतर्कता के निर्देश

**पटना।** जल संसाधन विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ घंटों में पटना में गंगा नदी के अपने उच्चतम जलस्तर को पार करने की संभावना है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने तथा संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों सोन, पुनपुन एवं दरधा के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। संभावित परिस्थितियों को देखते हुए प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग श्री संतोष कुमार मल्ल ने पटना सहित नालन्दा, भोजपुर, वैशाली, सारण, बेगूसराय, लखीसराय एवं जहानाबाद के जिला पदाधिकारियों को आवश्यक सावधानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन द्वारा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को संभावित जलस्तर वृद्धि के संबंध में सतर्क करने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी सूचना का व्यापक प्रसार करने को कहा गया है। इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया एवं माइकिंग के माध्यम से आम लोगों को लगातार जागरूक किया जाएगा।

आम नागरिकों से अपील की गई है कि नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें। विशेष रूप से नदी में स्नान करने, तैराकी करने, सेल्फी लेने अथवा नौकायन जैसी गतिविधियों से पूरी तरह परहेज करें। जलस्तर बढ़ने की स्थिति में नदी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित जिलों को बाढ़

आपदा प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसपीओ) के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की सहायता से प्रभावित अथवा जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जल संसाधन विभाग की सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने तथा तटबंधों की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। तटबंधों एवं संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति की सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को देने को कहा गया है। प्रशासन द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन पूरी सतर्कता बरतें तथा जलस्तर में वृद्धि अथवा बाढ़ से संबंधित किसी भी आधिकारिक सूचना एवं निर्देश का पालन करें

## एक नजर

### बाली में मयंक झा की शानदार जीत, अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका दरभंगा

**दरभंगा,एजेंसी।** इंडोनेशिया के बाली में आयोजित प्रतिष्ठित सीएफ कैनगो फाइट नाइट-40 प्रतियोगिता में दरभंगा के रामबाग निवासी मयंक झा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। उनकी इस उपलब्धि से बिहार और दरभंगा का नाम अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर गौरवान्वित हुआ है। मयंक झा रामबाग निवासी अमरकांत झा एवं वंदना झा के पुत्र हैं। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले में मयंक ने अपनी तकनीक, आत्मविश्वास और खेल कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। जीत के बाद मयंक ने स्टेज पर योग मुद्रा में अपनी जीत का जश्न मनाया। उनका यह अंदाज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। मयंक की सफलता की खबर मिलते ही परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ रामबाग और दरभंगा में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उनकी उपलब्धि पर दरभंगा राज के प्रबंधक पावन कुमार दत्ता, राजू मंडल, सुनील राय, सुशील कुमार सिंह, मनीष गिरी, अरुण शर्मा सहित शहर के कई लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। लोगों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर मयंक की सफलता दरभंगा के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।

### मुरादाबाद के आर्यन भट्ट ने जीता प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन डबल्स का खिताब

**मुरादाबाद।** प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में मुरादाबाद के आर्यन भट्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर डबल्स वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सतीश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से मेरठ में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में आर्यन की जोड़ी ने नोएडा के सार्थक सोम और आगरा के शुभम सोलंकी की जोड़ी को 15-11, 15-16 चैपियनशिप पर कब्जा जमाया। 29 अगस्त से शुरू हुई प्रतियोगिता में प्रदेशभर के करीब 600 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पूरे टूर्नामेंट में आर्यन ने दमदार खेल दिखाते हुए अपनी तकनीक का परिचय दिया। फाइनल में भी उन्होंने आक्रामक खेल के साथ विपक्षी जोड़ी को ज्यादा मौके नहीं दिए। आर्यन ब्रास सिटी जिमखाना स्थित अरवा बैडमिंटन एकेडमी में नियमित अभ्यास करते हैं। इससे पहले भी वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सतीश शर्मा ने आर्यन व उनके कोच को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अरवा बैडमिंटन एकेडमी के प्रयासों से आने वाले समय में जिले से और भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार होंगे, जो प्रदेश और देश स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे।

### नेता जी सुभाषचंद्र बोस सोनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम मुरादाबाद में होंगे बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी के मंडलीय ट्रायल

**मुरादाबाद।** प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में मुरादाबाद मंडल की टीमें उतारने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए नेता जी सुभाषचंद्र बोस सोनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम रामगंगा विहार, मुरादाबाद में इसी माह बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी के मंडलीय ट्रायल होंगे। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को पात्रता प्रमाणपत्र के साथ सक्षम स्तर से प्रमाणित जन्मतिथि प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा। क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सब जूनियर बालक-बालिका बैडमिंटन के मंडलीय ट्रायल सोनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 सितंबर को सुबह 11 बजे से होंगे। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 7 से 9 सितंबर तक गाजियाबाद में होगी। सब जूनियर बालक बास्केटबॉल के मंडलीय ट्रायल 5 सितंबर को सुबह 11 बजे होंगे। क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने आगे बताया कि इसकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 11 से 14 सितंबर तक आजमगढ़ में होगी। जूनियर बालक कबड्डी के मंडलीय ट्रायल नौ सितंबर को सुबह 11 बजे होंगे। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 7 से 9 सितंबर तक अयोध्या में प्रस्तावित है, वहीं सब जूनियर बालक कबड्डी के मंडलीय ट्रायल 22 सितंबर को सुबह 11 बजे होंगे। इसकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 24 से 26 सितंबर तक फिरोजाबाद में होगी। क्रीड़ाधिकारी ने खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ पहुंचने की अपील की है।

### कोपा अर्जेंटीना : लियोनेल मेसी के सम्मान में 10वें मिनट में रोका गया मुकाबला

**कोर्डोबा।** अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा के बाद कोपा अर्जेंटीना के मुकाबले में भावुक विदाई दी गई। वेलेज़ सार्सफील्ड और बोका जूनियर्स के बीच खेले गए मुकाबले को 10वें मिनट में कुछ देर के लिए रोककर मेसी को सम्मानित किया गया। एस्टाडियो मारियो अल्बर्टो केम्पेस में मौजूद दर्शक अपनी जगह से खड़े हो गए और अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी के सम्मान में तालियां बजाईं। मेसी ने 2026 फीफा विश्व कप के बाद अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को विराम देने का फैसला किया है। सम्मान समारोह के दौरान मेसी के पूर्व अंतरराष्ट्रीय साथी लियान्द्रो पारेदेस और मैनुएल लान्ज़िनी भी मैदान पर मौजूद थे। मुकाबला निर्धारित समय में गोलरहित 0-0 से बराबर रहा, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में बोका जूनियर्स ने 4-3 से जीत दर्ज की। रोसारियो के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के लिए 207 मैचों में 125 गोल और 68 असिस्ट के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत किया। उनके 21 साल लंबे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2022 में कतर में अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप खिताब दिलाना रही। मेसी ने 2021 और 2024 में अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका का खिताब भी दिलाया। 2021 की जीत के साथ अर्जेंटीना ने 28 साल से चले आ रहे अपने बड़े खिताबी सूखे को समाप्त किया था। यह दूसरी बार है, जब मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने इससे पहले 2016 में अर्जेंटीना के कप्तान के रूप में लगातार तीन फाइनल हारने के बाद संन्यास का ऐलान किया था।

# जूनियर एशिया कप: खिताब बचाने उतरेंगी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें

**मोकी (चीन),एजेंसी।** भारतीय जूनियर पुरुष और महिला हॉकी टीमें एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 में अपने-अपने खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन के मोकी में 4 से 13 सितंबर तक होने वाले इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम लगातार तीसरी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि पुरुष टीम रिकॉर्ड छठी बार ट्रॉफी अपने नाम करने का लक्ष्य रखेगी। भारतीय जूनियर महिला टीम ने पिछली दो प्रतियोगिताओं में खिताब जीता है और इस बार टीम की कप्तानी मिडफील्डर खैदेम शिलेम चानू करेंगी। टीम ने नए मुख्य कोच टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में लंबे समय तक योजनाबद्ध प्रशिक्षण किया है।

टूर्नामेंट की तैयारी के तहत भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया, जहां उसने स्कॉटलैंड की सीनियर महिला टीम, अमेरिका की अंडर-21, इंग्लैंड की अंडर-21 और बेल्जियम की अंडर-21 टीमों के खिलाफ सात मुकाबले खेले। इस दौरे से खिलाड़ियों को अलग-अलग खेल शैलियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का मौका मिला। कोच टिम व्हाइट ने कहा कि टीम ने परिस्थितियों के साथ अच्छी तरह तालमेल बैठा लिया है और दक्षिण कोरिया के खिलाफ शुरुआती मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में कई महीनों की तैयारी और इंग्लैंड दौरे के बाद टीम एशिया की मजबूत टीमों का सामना करने के लिए तैयार है। भारत एलीट पूल में है और 5 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। इसके बाद 6 सितंबर को मलेशिया, 8 सितंबर को जापान और 9 सितंबर को मेजबान चीन से मुकाबला होगा। भारतीय जूनियर पुरुष टीम भी गत चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में उतरेगी। भारत अब तक पांच बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीत चुका है, जिसमें पिछले तीन संस्करणों की ट्रॉफियां भी शामिल हैं। इस बार डिफेंडर अनमोल एक्का टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि नए मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज के कार्यकाल की शुरुआत खिताबी जीत के साथ करने का लक्ष्य होगा। टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम ने बेल्जियम में अंतरराष्ट्रीय अंडर-21 टीमों के खिलाफ अभ्यास और अनुभव हासिल किया। टीम ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स की मजबूत टीमों के खिलाफ मुकाबले खेले। इसके अलावा बेंगलुरु में मलेशिया की अंडर-21 टीम के खिलाफ अभ्यास मैच और डालियान में मेजबान चीन के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला खेलकर टीम ने अपनी तैयारियों को और मजबूत किया। चीन के खिलाफ आखिरी अभ्यास मुकाबले में भारत ने 8-2 से शानदार जीत दर्ज की थी। कोच फ्रेडरिक सोएज ने कहा कि चीन के खिलाफ आखिरी मैच से टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि डालियान में एक सप्ताह बिताकर खिलाड़ियों ने चीन की परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाया और अब टीम इंडोनेशिया के खिलाफ शुरुआती मुकाबले के लिए तैयार है।

# यूएस ओपन : टियाफोए तीसरे दौर में, इग्नासियो बुसे ने जीत के साथ दादा की विरासत को आगे बढ़ाया

**न्यूयॉर्क।** अमेरिका के फ्रांसेस टियाफोए ने बुधवार को जापान के क्वालीफायर रेई सकामोटो को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन 2026 के तीसरे दौर में जगह बना ली। वहीं पेरू के इग्नासियो बुसे ने पांच सेट के रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर इस ग्रैंड स्लैम में अपनी पहली जीत हासिल की और अपने दादा एडुआर्डो की विरासत को आगे बढ़ाया।

दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी टियाफोए ने लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच सकामोटो को 6-3, 7-6(7-2), 7-5 से हराया। टियाफोए की नजर न्यूयॉर्क में 23 साल से चले आ रहे अमेरिकी पुरुष चैंपियन के इंतजार को खत्म करने पर है। 28 वर्षीय टियाफोए ने मैच के पहले ही गेम में सकामोटो की सर्विस तोड़ी और पहला सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में वह जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लगातार दो डबल फॉल्ट ने सकामोटो को वापसी का मौका दे दिया। जापानी खिलाड़ी ने सेट को टाईब्रेक तक पहुंचाया, लेकिन दो बार यूएस ओपन सेमीफाइनल खेल चुके टियाफोए ने टाईब्रेक में शुरुआती पांच में से चार अंक जीतकर दो सेट की बढ़त बना ली।

सकामोटो ने मुकाबले में 18 ऐस लगाए, लेकिन 40 अनफोर्स्ड एरर भी किए। टियाफोए ने पहले दौर में पांच सेट तक चले मुकाबले के बाद इस बार सीधे सेटों में जीत दर्ज कर राहत की सांस ली। तीसरे दौर में उनका सामना कामिल माजचाक या वैलेन्तिन वाशेरो से होगा। पेरू के 32वीं वरीयता प्राप्त इग्नासियो बुसे ने भी बुधवार को अमेरिकी खिलाड़ी मार्कोस गिरोन को 3-6, 6-3, 6-3, 6-7(6-8), 6-1 से हराकर यूएस ओपन में अपनी पहली जीत दर्ज की। कोर्ट नंबर छह पर तीन घंटे 48 मिनट चले मुकाबले में जीत के साथ बुसे ने अपने परिवार के ग्रैंड स्लैम इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। 22 वर्षीय बुसे ने पांचवें सेट में मानसिक मजबूती दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मैच के बाद उन्होंने कहा, 'ऐसे हालात में शांत रहना मुश्किल होता है, लेकिन पांचवें सेट में मैंने मानसिक रूप से खुद को संभालने की कोशिश की। यह मानसिक लड़ाई थी और मैंने शांत रहने की कोशिश की। यह मेरे लिए बेहद खास पल है। बुसे ने अपने दादा एडुआर्डो को कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी जीत ने परिवार के यूएस ओपन से जुड़े करीब सात दशक पुराने रिश्ते को फिर जीवंत कर दिया। एडुआर्डो ने अपने जुड़वां भाई एनरिके के साथ टेनिस में पहचान बनाई थी और 1942 में इस टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा लिया था।

# एशियाई खेल : नीरज चोपड़ा की जगह यशवीर सिंह को भारतीय एथलेटिक्स टीम में मिली जगह

**नई दिल्ली,एजेंसी।** राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह को अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मिला है। चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह यशवीर को जापान में होने वाले आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को लुधियाना में एक प्रेस कांफ्रेंस में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले आइची-नागोया एशियाई खेलों के लिए 77 सदस्यीय भारतीय ट्रैक एवं फील्ड टीम की घोषणा की। यशवीर इस सत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और नीरज चोपड़ा के बाद भारतीय भाला फेंक में प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 85.41 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता था। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास छठे और अंतिम प्रयास में किया था।

यशवीर राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक का पदक जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। उनसे पहले काशीनाथ नाइक ने 2010 में कांस्य और नीरज चोपड़ा ने 2018 में स्वर्ण तथा 2026 में रजत पदक जीता था। यशवीर की इस सत्र में निरंतरता ने भी एशियाई खेलों के लिए उनका दावा मजबूत किया है। उन्होंने अब तक आठ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और इनमें से छह में 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका है। पिछले महीने भुवनेश्वर में आयोजित भारतीय ओपन में उन्होंने 82.94 मीटर के प्रयास के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। यह भारत में आयोजित विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर की पहली प्रतियोगिता थी। भाला फेंक से जुड़े परिवार से आने वाले यशवीर पूर्व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी राय सिंह के बेटे हैं। उन्होंने घरेलू स्तर पर अपनी पहचान तब बनाई थी, जब भारतीय अंडर-20 फेडरेशन कप में उन्होंने नीरज चोपड़ा का प्रतियोगिता रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब नीरज चोपड़ा के चोट के कारण बाहर होने के बाद यशवीर के पास एशियाई खेलों जैसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा साबित करने और भारतीय भाला फेंक में अगली बड़ी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने का मौका होगा।

# राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मप्र के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण सहित जीते तीन पदक

**भोपाल,एजेंसी।** पंजाब के लुधियाना स्थित गुरु नानक स्टेडियम में 01 से 03 सितंबर 2026 तक आयोजित 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इनमें कृष्ण चंद्र ने जैवलिन थ्रो में नया मीट रिकॉर्ड कायम कर स्वर्ण पदक जीतकर विशेष उपलब्धि हासिल की।

प्रतियोगिता के मुकाबलों में बॉयज जैवलिन थ्रो स्पर्धा में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी कृष्ण चंद्र ने 79.92 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता का नया मीट रिकॉर्ड भी कायम किया। कृष्ण चंद्र के शानदार प्रदर्शन से पहले इस स्पर्धा का मीट रिकॉर्ड 77.41 मीटर था, जो रोहित यादव ने वर्ष 2018 में बनाया था। कृष्ण चंद्र ने 79.92 मीटर का प्रदर्शन कर पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। हेप्टाथलॉन स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी नागर सिंह कनेश ने 4812 अंकों के शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नागर सिंह ने स्पर्धा के विभिन्न इवेंट्स में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम सफलता दिलाई। वहीं 1000 मीटर स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी रंगलाल डोडिया ने 2 मिनट 26.83 सेकंड के शानदार समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। रंगलाल ने अपनी गति और दमदार प्रदर्शन के साथ स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीतने वाले नागर सिंह कनेश, कृष्ण चंद्र एवं रंगलाल डोडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और कृष्ण चंद्र द्वारा नया मीट रिकॉर्ड कायम किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों की यह उपलब्धि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

# भारतीय निशानेबाजी आने वाले चार वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी : मेराज अहमद

**नई दिल्ली,एजेंसी।** दो बार के ओलंपियन मेराज अहमद खान को भरोसा है कि भारतीय निशानेबाजी आने वाले चार वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। 50 वर्षीय मेराज आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय शॉटगन टीम के 12 सदस्यीय तैयारी शिविर का हिस्सा हैं और इस बार एशियाई खेलों में अपने पहले पदक के लिए निशाना साधेंगे। मेराज ने साई मीडिया से बातचीत में कहा, 'देखिए, हर खिलाड़ी जीतने की उम्मीद करता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कम उम्मीदों के साथ प्रतियोगिता में उतरते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप उम्मीदों के साथ जाते हैं तो आप पहले ही भविष्य में पहुंच चुके होते हैं, आप वर्तमान में नहीं होते। आपको उस खास समय में जो करना है, उसी पर ध्यान केंद्रित करना होता है।

एशियाई खेलों से पहले शॉटगन निशानेबाजों का 15 दिवसीय तैयारी शिविर 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें ट्रैप और स्कीट के छह-छह, कुल 12 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। शॉटगन स्पर्धाएं 21 सितंबर से जापान के टोयोटा शहर स्थित आइची प्रीफेक्चुरल जनरल शूटिंग गैलरी में शुरू होंगी। 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय स्कीट निशानेबाज बने मेराज ने दो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह तीन दशक से अधिक समय से शीर्ष स्तर पर निशानेबाजी कर रहे हैं और अभी भी अपने खेल को लेकर उतने ही उत्साहित हैं। एशियाई खेलों की तैयारियों पर मेराज ने कहा, 'हम एशियाई खेलों के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हमारे शॉटगन शिविर में पूरी टीम मौजूद है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हमारे लिए हर चीज की व्यवस्था की है। हमारे पास शारीरिक और कंडीशनिंग प्रशिक्षक, फिजियो, विदेशी कोच रिकार्डो फिलिपेली, मुख्य कोच अमरिंदर सिंह चीमा और अन्य सभी सहयोगी स्टाफ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि तैयारी के लिए यह बहुत उपयोगी शिविर है और इंशाअल्लाह, एशियाई खेलों में इसका फायदा मिलेगा।' 1994 में निशानेबाजी करियर शुरू करने वाले मेराज ने भारतीय शॉटगन के भविष्य को लेकर भी बड़ा भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'अगर हम शॉटगन की बात करें तो स्कीट और ट्रैप दोनों बहुत अच्छी तरह आगे आए हैं और आने वाले समय में यह और बेहतर होगा।' मेराज ने कहा, 'इस समय भारत सरकार, खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो मंच तैयार किए हैं, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम और मंच आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दुर्भाग्य से हमारे समय में ये सभी कार्यक्रम नहीं थे, इसलिए शायद हमें ओलंपिक या विश्व कप पदक जीतने में थोड़ा समय लगा।'

# भारत से भिड़ने के एक महीने बाद जापान और सिंगापुर से मैत्री मुकाबले खेलेगी ब्राजीलियाई फुटबॉल टीम

**नई दिल्ली,एजेंसी।** पांच बार का विश्व चैंपियन ब्राजील नवंबर में एशियाई टीमों के खिलाफ अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएगा। ब्राजील फुटबॉल संघ ने गुरुवार को घोषणा की कि टीम नवंबर के अंतरराष्ट्रीय विंडो में जापान और सिंगापुर के खिलाफ मैत्री मुकाबले खेलेगी। कार्लो एंसेलोटी की टीम सितंबर-अक्टूबर की अंतरराष्ट्रीय विंडो में ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ मुकाबले खेलेगी। इसके बाद नवंबर में ब्राजील का सामना 14 नवंबर को जापान और 17 नवंबर को सिंगापुर से होगा। दोनों मुकाबले सिंगापुर के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे।

कोच एंसेलोटी ने कहा कि सिंगापुर में होने वाले ये मैत्री मुकाबले आने वाले वर्षों के लिए ब्राजील की राष्ट्रीय टीम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जापान और सिंगापुर के खिलाफ मुकाबलों से टीम को अलग-अलग परिस्थितियों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि टीम अपनी पहचान मजबूत करने और विकल्पों का विस्तार करने पर काम कर रही है। लक्ष्य संतुलन के साथ लगातार सुधार करना और आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए टीम को तैयार करना है। ब्राजील और जापान के बीच मुकाबला 2026 फीफा विश्व कप के अंतिम-32 दौर की भिड़ंत की पुनरावृत्ति भी होगा। उस मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अंतिम क्षणों में गोल कर ब्राजील को 2-1 से जीत दिलाई थी। जापान के मुख्य कोच हाजिमे मोरियासु ने कहा कि टीम इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जापान अगले साल जनवरी में होने वाले एएफसी एशियाई कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। सिंगापुर में फुटबॉल को लेकर उत्साह का जिक्र करते हुए मोरियासु ने कहा कि विश्व कप के दौरान सिंगापुर और अन्य एशियाई देशों के कई लोगों ने जापान का समर्थन किया था। उन्होंने ऐसे फुटबॉल प्रेमी देश में खेलने का मौका मिलने पर खुशी जताई। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सिंगापुर और पैराग्वे के बीच 13 नवंबर को नेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से होगी। इसके अगले दिन जापान और ब्राजील आमने-सामने होंगे।

# बांग्लादेश की लेक सिटी रंगामती में बरसात की मार, कपताई झील पर बना हैंगिंग ब्रिज डूबा

**ढाका ( बांग्लादेश ),एजेंसी।** देश में लेक सिटी के नाम से मशहूर और प्रमुख पर्यटक स्थल रंगामती में कपताई झील पर बना हैंगिंग ब्रिज (झूलता पुल) डूब गया है। कई दिनों की भारी बारिश और पहाड़ियों से आए पानी की वजह से कपताई झील का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बांग्लादेश पर्यटन निगम ने सुरक्षा कारणों से पुल के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। प्रवेश द्वार पर लाल झंडा लगाते हुए बांस की बैरिकेडिंग की गई है। रंगामती देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में चटगांव डिवीजन में आता है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पुल के बंद हो जाने से जानकारी के अभाव में पहुंच रहे पर्यटकों का निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी झटका लगा है। यह झील बांग्लादेश की सबसे बड़ी कृत्रिम (मानव निर्मित) झील है। यह कर्णफुली नदी पर बने कपताई बांध के कारण अस्तित्व में आई। 335 फीट लंबे खूबसूरत पुल को रंगामती पर्यटन का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। यह पुल झील के बीच में स्थित दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ता है। पुल बंद हो जाने से स्थानीय बोट टर्मिनल पर इंजन वाली 100 से ज्यादा नावें बेकार खड़ी हैं। पारंपरिक कपड़े, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प बेचने वाली दुकानें भी ग्राहकों

के बिना सूनी हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि बिक्री लगभग शून्य हो गई है। स्थानीय बोट ओनर्स एसोसिएशन के लीज होल्डर मोहम्मद फखरुल इस्लाम ने कहा कि यह समय उनकी आजीविका के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा, 'इस सीजन में आने वाले पर्यटकों की वजह से हमारे परिवारों का साल भर का खर्च चलता है। लेकिन पुल के डूबने के बाद से हमारी कमाई पूरी तरह बंद हो गई है। अगर हालात ऐसे ही रहे, तो हमें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।' होटल मालिक मोहम्मद सुमन मिया ने कहा कि हैंगिंग ब्रिज रंगामती आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षणों में से एक है। उन्होंने कहा, 'बहुत से पर्यटक पुल देखने के लिए ही रंगामती आते हैं। इसके डूबने के बाद से हर दिन होटल बुकिंग रग हो रही हैं। पर्यटकों की संख्या में कमी से होटलों, मोटलों और रेस्तरां को नुकसान हो रहा है। रंगामती टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मैनेजर आलोक बिकास चकमा ने बताया कि भारी बारिश और पहाड़ियों से बहकर आए पानी की वजह से कपताई झील का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पुल पानी में डूब गया। उन्होंने कहा, ' पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमने लाल झंडे लगा दिए हैं और बांस के बैरियर लगाकर रास्ता बंद कर दिया है।' रंगामती जिला परिषद के चेयरमैन दीपन तालुकदार दीपू ने बताया कि एक नए पुल के निर्माण के लिए पहले ही सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि ज्यादा ऊंचाई पर एक नए, आधुनिक पुल का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा ।'

## एक नजर

### इजराइल ने चार लेबनानी बंदियों की रिहाई टाली, अब शुक्रवार सुबह होगा हस्तांतरण

**बेरूत,एजेंसी।** इजराइल की जेलों में बंद चार लेबनानी नागरिकों को लेबनान को सौंपने की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है। लेबनानी प्रसारक एलबीसीआई के अनुसार, चारों बंदियों को अब शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे लेबनान को सौंपे जाने की उम्मीद है। इन चारों की रिहाई इजराइल और लेबनान के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है। इसके तहत इजराइल पांच लेबनानी नागरिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुआ है। बदले में लेबनान ने 1980 के दशक में अगवा कर मारे गए लेबनानी यहूदी समुदाय के प्रमुख लोगों के अवशेषों की तलाश और उन्हें वापस लाने के प्रयासों में सहयोग किया है। पांच बंदियों में से पहले व्यक्ति मालेक गाजी को गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की मदद से लेबनानी सेना को सौंप दिया गया। उन्हें दक्षिणी लेबनान के नाकूरा सीमा क्षेत्र में रेड क्रॉस के हवाले किया गया, जिसके बाद लेबनानी अधिकारियों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाकी चार बंदियों को गुरुवार शाम रिहा किया जाना था, लेकिन प्रक्रिया में देरी हो गई। अब उनके शुक्रवार सुबह हस्तांतरण की संभावना है। दरअसल, अमेरिका की मध्यस्थता से हुए प्रयासों के बाद यह समझौता आगे बढ़ा है और दोनों देशों के बीच अन्य नागरिक मुद्दों पर भी बातचीत की उम्मीद जगी है।

### असद युग के रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू, सीरिया ने उठाया बड़ा कदम

**दमिश्क।** सीरिया ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासनकाल से जुड़े रासायनिक हथियारों और उनसे संबंधित सामग्रियों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के प्रतिनिधि इब्राहिम ओलाबी ने सुरक्षा परिषद को इसकी जानकारी दी। यह कदम दिसंबर 2024 में असद सरकार के पतन के बाद सीरिया की नई सत्ता की ओर से रासायनिक हथियारों के मुद्दे पर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओलाबी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय रासायनिक हथियार निगरानी संस्था ऑर्गनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स (ओपीसीडब्ल्यू) द्वारा चिन्हित सामग्रियों को नष्ट करने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन के तहत सीरियाई क्षेत्र में रासायनिक सामग्रियों के विनाश की यह पहली ऐसी प्रक्रिया है। ओपीसीडब्ल्यू की एक विशेषज्ञ टीम ने मई 2026 में सीरियाई अधिकारियों के सहयोग से देश में पहले से घोषित नहीं किए गए रासायनिक हथियारों, रासायनिक पदार्थों, उपकरणों और संबंधित दस्तावेजों का पता लगाया था। सीरिया में 2013 के बाद घोषित रासायनिक हथियारों के विनाश की अंतरराष्ट्रीय निगरानी शुरू हुई थी, लेकिन बाद में अतिरिक्त सामग्रियों और गतिविधियों को लेकर सवाल बने रहे। नई सीरियाई सरकार ने अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों के साथ सहयोग बढ़ाया है।

### ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी, आईआरजीसी प्रमुख बोले- शादी समारोह पर हमले का हिसाब होगा

**तेहरान।** ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के प्रमुख अहमद वहीदी ने दक्षिणी ईरान में एक शादी समारोह के दौरान हुए घातक हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस हमले में मारे गए लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी हमले में एक शादी समारोह के दौरान चार लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि उसके सैन्य अभियान का लक्ष्य ईरानी सैन्य ढांचा था। आईआरजीसी प्रमुख वहीदी ने सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में कहा कि हमले में मारे गए लोगों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और इसके लिए निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। उनका यह बयान दोनों देशों के बीच पहले से जारी सैन्य तनाव के और बढ़ने की आशंका के बीच आया है। रिपोर्टों के मुताबिक, दक्षिणी ईरान में हुए हमले में कम से कम चार नागरिकों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। घटना को लेकर ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

### लेबनान की मदद के बाद इजराइल का बड़ा फैसला, पांच लेबनानी नागरिक बंदियों को करेगा रिहा

**तेल अवीव।** इजराइल ने लेबनान के साथ चल रही बातचीत के बीच दक्षिणी लेबनान से हिरासत में लिए गए पांच लेबनानी नागरिकों को रिहा करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह कदम लेबनान की ओर से लेबनानी यहूदी समुदाय के दिवंगत नेताओं के अवशेषों की तलाश और उन्हें वापस लाने के प्रयासों में हाल में की गई मदद के बाद उठाया गया है। इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने जमीन पर अभियान सहित कई स्तरों पर इन अवशेषों की तलाश के प्रयास किए। जांच के बाद यह सामने आया कि हिरासत में लिए गए पांचों लोग आम नागरिक हैं और उनका किसी आतंकवादी संगठन से संबंध नहीं है। उनके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कार्यालय ने बताया कि नेतन्याहू ने अधिकारियों को लेबनान के यहूदी समुदाय के उन नेताओं के शवों की तलाश और वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें 1980 के दशक के मध्य में कथित तौर पर अगवा कर हत्या कर दी गई थी। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने पांच में से एक बंदी को लेबनान को सौंपे जाने की पुष्टि की है। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देश बंदियों की रिहाई के साथ-साथ लेबनानी और इजराइली यहूदी नागरिकों के अवशेषों की पहचान एवं वापसी को लेकर भी अलग-अलग स्तर पर बातचीत कर रहे हैं।

### नेपाल आपदा में मारे गए लोगों की याद में 7 सितंबर को राष्ट्रीय शोक की घोषणा

**काठमांडू।** नेपाल में आई भीषण आपदा में जान गंवाने वालों के सम्मान में सरकार ने 7 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठक ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि गुरुवार दोपहर हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में घटना के 13वें दिन 7 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिन नेपाल के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ विदेशों में स्थित नेपाली दूतावासों और राजनयिक मिशनों में नेपाली झंडा आधा झुकाया जाएगा। इसी तरह नेपाल सरकार ने जेन जी आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक में 8 सितंबर को हुए जेन जी आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए जेन जी युवाओं की याद में सार्वजनिक अवकाश देने की घोषणा की है।

### फिलिस्तीनियों से गाजा को खाली कराना ही समस्या का एकमात्र हल: इजराइली रक्षामंत्री काट्ज

**तेल अवीव,एजेंसी।** इजराइल के रक्षामंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल अभी भी फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाना चाहता है। इस इलाके से फिलिस्तीनियों को हटाए बिना गाजा समस्या का असली समाधान नहीं होगा। इजराइल अभी भी इस मोर्चे पर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ उस योजना को रोका है। इस योजना को मानवाधिकार कार्यकर्ता एथनिक क्लींजिंग (किसी खास नस्ल या समुदाय के लोगों को हटाने या खत्म करने की कार्रवाई) मानते हैं।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, काट्ज ने बुधवार को इजराइल की न्यूज वेबसाइट वाई नेट के विचारोत्तेजक सम्मेलन में गाजा समस्या पर खुलकर चर्चा की। काट्ज ने कहा, ' गाजा से फिलिस्तीनी हट जाएं तो समस्या हल हो जाएगी।' उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में इजराइल के इस विचार का समर्थन कर चुके हैं। ट्रंप ने तो एक बार यहां तक कहा कि एक बार फिलिस्तीनियों को हटा दिए जाने के बाद अमेरिका इस इलाके पर कब्जा कर लेगा और उस जमीन का मालिक बन जाएगा। काट्ज ने कहा कि इजराइल गाजा पर हर तरीके से कब्जा करने के लिए तैयार है, लेकिन मिस्र फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विस्थापित फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने वाले अन्य देशों को अमेरिकी समर्थन की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, 'फिलहाल,ट्रंप ने इसे रद नहीं किया है। उन्होंने

इसे स्थगित कर दिया है। काट्ज ने कहा कि इस पर उनसे लगातार चर्चा हो रही है। काट्ज ने यह सभी के लिए अच्छा होगा। इस अभियान में अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन साल में अमेरिका ने इजराइल को लगभग 25 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी है। उसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजराइल का बचाव किया है। इसमें गाजा में हुए अत्याचारों की जांच कर रहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।

### मेहरगढ़ पर ड्रोन हमला और मुस्तांग गार्डन को तबाह करना बलोचिस्तान में बढ़ते जुल्म की निशानी: नवाब असलम रायसानी

**क्वेटा ( बलोचिस्तान ) पाकिस्तान।** बलोचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाब असलम रायसानी ने संघीय सरकार के सैन्य अभियान के दौरान मेहरगढ़ पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मेहरगढ़ किसी एक व्यक्ति का घर नहीं है, बल्कि बलोचिस्तान का एक अहम राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और कबीलाई सेंटर है। इसे बार-बार निशाना बनाया जाना चिंताजनक और निंदनीय है।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नवाब असलम रायसानी ने कहा कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान की ऐतिहासिक विरासत, कबीलाई एकता और शांति की निशानी है। ऐसे सेंटर और लोगों के घरों को निशाना बनाना राष्ट्रीय और ऐतिहासिक विरासत का अपमान है। इससे लोगों में नफरत की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मेहरगढ़ की घटना समेत बलोचिस्तान में बढ़ते बल प्रयोग से यह डर और मजबूत हो रहा है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक और लोकतांत्रिक संघर्ष के रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकारी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि इतिहास राष्ट्रीय धरोहर और लोगों के घरों के अपमान को कभी नहीं भूलता। पूर्व मुख्यमंत्री नवाब असलम रायसानी ने कहा कि सत्ताधारी बलोच विद्रोह के पीछे भारत का हाथ ठहराते हैं। यह आरोप बेबुनियाद है। विद्रोह नागरिकों पर थोपे गए दबाव, जुल्म और अन्याय से पैदा

होते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ काटे जा सकते हैं। बगीचे लगाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में पैदा हुए अविश्वास और नफरत के वृक्षों को ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर सरकार सच में बलोचिस्तान में शांति चाहती है, तो उसे विरोध को सिर्फ 'देशद्रोह' कहने के बजाय उन बुनियादी कारणों को खत्म करना होगा जो लोगों को विरोध करने के लिए मजबूर करते हैं।

नवाब असलम रईसानी ने कहा कि बलोचिस्तान एक ऐतिहासिक जमीन है और लगातार ताकत के इस्तेमाल से हालात और मुश्किल हो सकते हैं। देश और कबायली अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और राजनीतिक संघर्ष जारी रहना चाहिए, जबकि सरकार को ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय बातचीत, राजनीतिक बातचीत और लोकतांत्रिक समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के लोगों और राज्य दोनों के हित में है कि वे तनाव बढ़ाने के बजाय शांति, राजनीतिक बातचीत, आपसी विश्वास और हालात में सुधार का रास्ता अपनाएं। पक्की शांति ताकत से नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान, राजनीतिक समावेश और बातचीत से ही कायम की जा सकती है।

### नेपाल त्रासदी के बाद बिजली का निर्यात प्रभावित, बांग्लादेश को आपूर्ति बंद और भारत को कटौती

**काठमांडू।** रसुवा के भोटेकोशी क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचने के बाद नेपाल की बिजली निर्यात व्यवस्था प्रभावित हुई है। बांग्लादेश को बिजली निर्यात पूरी तरह रोक दिया गया है, जबकि भारत को भेजी जा रही बिजली में कटौती की गई है।

बांग्लादेश को बिजली निर्यात के लिए समझौता किए गए चिलिमे और त्रिशूली जलविद्युत परियोजनाओं को भोटेकोशी बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। इसके कारण इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली बांग्लादेश भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। नेपाल इन दोनों परियोजनाओं से उत्पादित 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को निर्यात करता था। बाढ़ से उत्पादन और प्रसारण संरचनाओं को नुकसान पहुंचने के बाद फिलहाल यह निर्यात रोक दिया गया है। नेपाल को भारत और बांग्लादेश दोनों को मिलाकर करीब 1,200 मेगावाट तक बिजली निर्यात की अनुमति मिली हुई थी, लेकिन भोटेकोशी में आई बाढ़ से रसुवा और नुवाकोट के कई जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। बिजली उत्पादन घटने के कारण नेपाल को भारत की ओर होने वाले बिजली निर्यात में भी कटौती करनी पड़ी है। प्रभावित परियोजनाओं से उत्पादन दोबारा शुरू नहीं होने तक भारत को बिजली आपूर्ति पर भी दबाव बना रहने की संभावना है। बाढ़ से नेपाल विद्युत प्राधिकरण और निजी क्षेत्र की 12 जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के ढांचे के साथ-साथ संचालन में रही परियोजनाएं भी बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ प्रभावित परियोजनाओं में बिजली उत्पादन पुनः शुरू होने तक देश की निर्यात योग्य बिजली की उपलब्धता कम रहेगी और बिजली निर्यात पर दबाव बना रहेगा।

## एक नजर

### पश्चिमी यूपी में राजनीतिक फायदे के लिए साम्प्रदायिकता व जातिगत विभाजन पैदा कर रही भाजपा : अखिलेश यादव

**लखनऊ,एजेंसी।** समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजनीतिक फायदे के लिए संपन्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिकता व जातिगत विभाजन पैदा करके सिस्टेमेटिक तरीके से अर्थव्यवस्था पर चोट की है। भाजपा सरकार ने खेती-किसानी, उद्योग चौपट कर दिया। हैंडीक्राफ्ट-एक्सपोर्ट बर्बाद कर दिया। सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हो रही है। खेल को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। शिक्षा छीनी जा रही हैं। कला के वैकल्पिक व्यवसाय पर 18 राउंड गोली मारी जा रही है। श्रमिक असंतोष को बढ़ने दिया जिससे कि कारखाने खत्म हो जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। किसानी की जमीन को छीनने का प्रयास हो रहा है। जीएसटी के भ्रष्टाचार से छोटे व्यापारियों को मारा जा रहा है। खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। स्कूल व जौहर यूनिवर्सिटी बंद करने की साजिश हो रही है। नारी को डराकर घर बैठाने की साजिश हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दस्तकारी-हस्तकारी को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। अमेरिकी डील का सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ है। क्योंकि यहाँ के किसान भी मारे गये और टैरिफ बढ़ने से मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ और बाकी जगह के कारखाने और हस्तशिल्प भी। श्रमिकों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर कारोबारियों को डराया गया। गौतम बेटी को मारकर पीडीए पर अत्याचार किया। पुलिस से राठी के मुँह पर लात मरवाई और जाटव भाई के साथ जुल्म-ज्यादती की। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए 2027 के चुनाव में सबसे अप्रत्याशित परिणाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटों का सौदा कोई नहीं कर पायेगा, क्योंकि 10-15 सालों से लगातार हो रहे उत्पीड़न, उपेक्षा, अत्याचार से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर-श्रमिक, हस्तकार, युवा, महिला, खिलाड़ी, कलाकार, दुकानदार, व्यापारी-कारोबारी, एक्सपोर्टर, उद्योगपति सब जागरूक हो गये हैं, वो अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। यह जानकारी गुरुवार को सपा मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म के साथ न्याय के लिए खड़ा रहकर अन्याय के विरूद्ध लड़ने का उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनका जीवन प्रेरणास्पद और उनका संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के संपूर्ण जीवन में लोकभावना सर्वोपरि थी। उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई। उनकी सोच, कर्म और व्यक्तित्व अलौकिक है।

### मद्रास हाई कोर्ट ने स्टालिन की याचिका की खारिज, टीवीके विधायक वी.एस. बाबू की जीत बरकरार

**चेन्नई,एजेंसी।** मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से तमिलगा वेत्रि कड़गम (टीवीके) उम्मीदवार वी.एस. बाबू की जीत को चुनौती देने वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। दरअसल, हाल ही में संपन्न 2026 विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ने वाले एम.के. स्टालिन को वी.एस. बाबू के हाथों 8,795 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बाबू को विजेता घोषित किए जाने के बाद स्टालिन ने मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था। स्टालिन के आवेदन पर निर्वाचन क्षेत्र की 14 ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि जांच के दौरान कुछ मशीनें खराब हो गईं और छह मतदान केंद्रों पर वीवीपैट पर्चियों के मिलान में अनियमितताएं सामने आईं। इसके आधार पर सभी ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की दोबारा जांच कराने तथा वी.एस. बाबू की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल उठाया कि स्टालिन ने मामले को चुनाव याचिका के रूप में क्यों दाखिल नहीं किया। स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव समाप्त होने के 45 दिन बाद निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की जांच की, जिससे चुनाव याचिका दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई।

# जन्माष्टमी पर देशभर में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के व्यापार की संभावना

**नई दिल्ली,एजेंसी।** रक्षाबंधन पर हुए बड़े कारोबार के बाद अब श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस वर्ष देशभर में चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक के व्यापार होने की संभावना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने यह अनुमान विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में संभावित बिक्री, धार्मिक एवं घरेलू खरीदारी, मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर होने वाले व्यय, देशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों तथा धार्मिक पर्यटन से जुड़े खर्चों के आधार पर जारी किया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव केवल श्रद्धा और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, परंपरा, सामाजिक सहभागिता और आर्थिक गतिविधियों का अद्भुत संगम भी है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी ऐसा पर्व है, जिसमें आस्था सीधे आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तित होती दिखाई देती है।

खंडेलवाल ने कहा कि जन्माष्टमी केवल आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारत की 'सनातन अर्थव्यवस्था' की जीवंत शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि पूजा-अर्चना से लेकर धार्मिक पर्यटन तक, जन्माष्टमी करोड़ों लोगों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा महापर्व है। कैट महामंत्री ने कहा कि भारत त्योहारों का देश है और देश का प्रत्येक पर्व केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि व्यापक आर्थिक गतिविधियों

का भी आधार बनता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान का प्रभाव त्योहारों के बाजारों में अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि अब उपभोक्ता बड़ी संख्या में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापार, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर पूजा सामग्री से लेकर सजावटी वस्तुओं और धार्मिक उत्पादों तक अधिकांश मांग स्वदेशी वस्तुओं की है। खंडेलवाल ने कहा कि जन्माष्टमी से जुड़ा प्रत्येक अनुष्ठान और आयोजन किसी न किसी रूप में लाखों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। किसान, दुग्ध उत्पादक, फूल उत्पादक, मिठाई के कारोबारी, वस्त्र विक्रेता, मूर्तिकार, कारीगर, महिला उद्यमी, ट्रांसपोर्टर, होटल व्यवसायी, रेस्तरां संचालक तथा सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग इस पर्व से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। वहीं, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया के अनुसार वर्ष 2024 में जन्माष्टमी के अवसर पर देशभर में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था, जबकि वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

इस वर्ष उपभोक्ता मांग में हुई वृद्धि, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन, त्योहारों के बढ़ते सामाजिक विस्तार, धार्मिक पर्यटन में वृद्धि तथा आधुनिक रिटेल एवं डिजिटल खरीदारी के विस्तार को देखते हुए लगभग 30 फीसदी वृद्धि के साथ ये व्यापार 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। भरतिया ने कहा कि कैट द्वारा किए गए आकलन के अनुसार जन्माष्टमी से जुड़े व्यापार में प्रमुख हिस्सेदारी मिठाई, माखन-मिश्री एवं डेयरी उत्पाद 20 फीसदी, पूजा सामग्री, धूप-अगरबत्ती, पंचामृत एवं पूजन किट 10 फीसदी, फूल, मालाएं एवं सजावट सामग्री 12 फीसदी, पारंपरिक परिधान एवं वस्त्र 10 फीसदी, फल, सूखे मेवे एवं प्रसाद सामग्री 10 फीसदी, लड्डू गोपाल की मूर्तियां, झूले एवं श्रृंगार सामग्री 8 फीसदी, उपहार, खिलौने एवं घरेलू सजावटी सामग्री 5 फीसदी, धार्मिक पर्यटन, होटल, परिवहन व अन्य सेवाएं 15 फीसदी, जबकि अन्य उपभोक्ता वस्तुएं 10 फीसदी शामिल हैं।

## पीएम मोदी के आपत्तिजनक पोस्टर मामले में अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा को हाई कोर्ट की फटकार, 24 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

**कोलकाता।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपत्तिजनक कार्टून वाले पोस्टर को प्रदर्शन के दौरान दिखाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए 24 दिसंबर तक पुलिस की किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है, से संरक्षण प्रदान किया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पोस्टर को 'अशोभनीय' बताते हुए कहा कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति की ओर से इस तरह का पोस्टर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाना खराब रुचि को दर्शाता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित या सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि एक स्थापित अभिनेत्री होने के नाते श्रीलेखा मित्रा को सार्वजनिक आचरण को लेकर अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने टिप्पणी की कि इस तरह का पोस्टर लोगों की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है और इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस घटना को लेकर कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसके बाद अदालत ने आनंदपुर थाने को निर्देश दिया कि अभिनेत्री के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों को एकत्र कर उनका समेकित रूप से जांच की जाए। अदालत ने श्रीलेखा मित्रा को जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया। पुलिस को पूछताछ के लिए बुलाने से कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देने को कहा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभिनेत्री जांच में सहयोग नहीं करती हैं, तो उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा वापस ली जा सकती है। मामला जुलाई में कथित नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन का आयोजन कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था। मध्य कोलकाता के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इसी दौरान श्रीलेखा मित्रा को प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक कार्टून वाला पोस्टर हाथ में लिए देखा गया था। घटना के बाद भाजपा नेता काया घोष ने आनंदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद विधाननगर साइबर अपराध थाने समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी इसी मामले को लेकर शिकायतें दर्ज की गईं। भाजपा ने अभिनेत्री की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

## सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, सोना और चांदी की फीकी पड़ी चमक

**नई दिल्ली,एजेंसी।** सर्राफा बाजार में कमजोरी का दौर लगातार जारी है। आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोना और चांदी में जबरदस्त गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में सोना आज 1,900 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,070 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत आज 2,400 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,620 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गई है। चांदी भी आज ज्यादातर सर्राफा बाजार में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो गया है।

भाव में बदलाव होने की वजह से देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,52,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,39,340 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार में 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,52,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,490 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,52,060 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,390 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,39,340 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,39,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,52,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,39,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,52,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,39,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

## जामिया रजिस्ट्रार के समर्थन में उतरे छात्र, कहा जामिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ़ हो कड़ी कार्रवाई

### प्रो. महताब आलम रिज़वी के पक्ष में छात्र हुए एकजुट , कहा—आरोपों की सच्चाई कानूनी प्रक्रिया से हो तय

**डॉ. एम रहमतुल्लाह**

**नई दिल्ली।** जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बड़ी संख्या में छात्रों ने जामिया नगर थाने पहुंचकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. महताब आलम रिजवी के खिलाफ कथित रूप से प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक और मानहानिकारक आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज करने तथा पूरे मामले की जांच की मांग की। छात्रों ने भूपेंद्र पाल सिंह चौहान और हारिस उल हक के खिलाफ शिकायत देते हुए प्रसारित सामग्री की सत्यता और उसके स्रोत की जांच की मांग की। छात्रों का आरोप है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से रजिस्ट्रार के संबंध में ऐसी सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिसमें पर्याप्त तथ्यों और संदर्भ का अभाव है। उन्होंने पुलिस से यह पता लगाने की मांग की कि सामग्री कहां से प्रसारित हुई, उसमें किए गए दावे कितने सत्य हैं और क्या इस प्रक्रिया में किसी कानून का उल्लंघन हुआ है। छात्रों ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार के पक्ष में पहले ही एक सिविल अदालत का आदेश आ चुका है। उनके अनुसार, अदालत ने विवादित आरोपों से संबंधित सामग्री के प्रसार पर रोक लगाई है तथा रजिस्ट्रार की नियुक्ति और पदोन्नति को विश्वविद्यालय की निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत किए जाने का उल्लेख किया है। आदेश में रोक के बावजूद संबंधित सामग्री के आगे प्रसार पर अवमानना की कार्रवाई की बात भी कही गई है।

**आलोचना पर रोक नहीं, लेकिन आरोपों की सत्यता जरूरी**

प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य वैध आलोचना को रोकना नहीं, बल्कि गंभीर आरोपों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले उनकी सत्यता की जांच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति, पदोन्नति और प्रशासनिक निर्णय जैसे विषय विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं और इनके संबंध में शिकायत के लिए उचित संस्थागत मंच उपलब्ध हैं। छात्रों ने सोशल मीडिया पर अधूरी अथवा अपुष्ट सूचनाओं के तेजी से प्रसार पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि डिजिटल माध्यमों के जरिए कोई भी आरोप कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है, जबकि उसकी तथ्यात्मक जांच में समय लग सकता है। छात्रों के मुताबिक, रजिस्ट्रार से संबंधित प्रसारित सामग्री में कई बातों को उनके मूल संदर्भ से अलग करके पेश किया गया है। छात्रों ने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी पर लगाए गए अप्रमाणित आरोप केवल संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करते, बल्कि पूरे संस्थान की छवि पर भी असर डालते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा की रक्षा को छात्रों और विश्वविद्यालय समुदाय की साझा जिम्मेदारी बताया। पुलिस से छात्रों की मुख्य मांग है कि रजिस्ट्रार के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उन्हें प्रसारित करने में इस्तेमाल सामग्री की कानूनी दायरे में जांच की जाए। यदि जांच में किसी कानूनी प्रावधान के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों से जुड़े विवादों का समाधान आरोप-प्रत्यारोप के बजाय तथ्यों, प्रमाणों, निष्पक्ष जांच और निर्धारित कानूनी एवं संस्थागत प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। उनका कहना है कि सोशल मीडिया महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन इसकी व्यापक पहुंच के कारण अपुष्ट जानकारी के तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए किसी भी आरोप को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच आवश्यक है।

## 5जी एंबुलेंस से किडनी ट्रांसप्लांट तक, ईएसआईसी सनथ नगर बना डिजिटल हेल्थ का मॉडल सेंटर, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचेगी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा

**हैदराबाद/देहरादून।** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का सनथ नगर परिसर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, उन्नत उपचार और डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में एक प्रमुख मॉडल संस्थान के रूप में उभर रहा है। टेलीमेडिसिन से 5जी एंबुलेंस तक, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की राह आसान करेगा। 1,044 बेड की एकीकृत स्वास्थ्य सुविधा, किडनी ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेवाओं,5जी-सक्षम एंबुलेंस और डिजिटल मरीज सेवाओं के साथ यह केंद्र ईएसआईसी नेटवर्क में अपनी अलग पहचान बना रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पीआईबी देहरादून की ओर से हैदराबाद के प्रेस दौरे पर आए उत्तराखंड के 15 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सनथ नगर का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल की चिकित्सा, शैक्षणिक, प्रयोगशाला और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

उत्तराखंड से आए मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को ईएसआईसी सनथ नगर परिसर का दौरा कर यहां संचालित चिकित्सा सुविधाओं, डिजिटल हेल्थ सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों की जानकारी ली। अस्पताल की डीन डॉ. एस. सीथालक्ष्मी ने प्रतिनिधिमंडल को संस्थान की उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी ।प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि ईएसआईसी सनथ नगर

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हो रहा है।

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में ईएसआईसी सनथ नगर का डिजिटल हेल्थ मॉडल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 5जी-सक्षम एंबुलेंस, टेलीमेडिसिन और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के जरिए अस्पताल ने आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का ऐसा मॉडल विकसित किया है, जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है। दौरे के दौरान 5जी-सक्षम एंबुलेंस विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस तकनीक के माध्यम से मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ा जा सकता है और आवश्यक चिकित्सा निगरानी शुरू की जा सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ इलाकों में दुर्घटना, हृदय संबंधी आपात स्थिति तथा गंभीर मरीजों के लिए ऐसी व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। ईएसआईसी सनथ नगर में किडनी ट्रांसप्लांट सहित सुपर स्पेशियलिटी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा कैंसर, टीबी, डायबिटीज और किडनी रोगों के उपचार के साथ इन क्षेत्रों में शोध पर भी जोर दिया जा रहा है। आधुनिक प्रयोगशालाओं और चिकित्सा उपकरणों की जानकारी भी प्रतिनिधिमंडल को दी गई। प्रतिनिधिमंडल को टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों को दूरस्थ मरीजों से जोड़ने की संभावनाओं से भी अवगत कराया गया। इससे उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को लाभ मिल सकता है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक पहुंच में भौगोलिक बाधाएं आती हैं। दौरे का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और व्यवस्थाओं को समझना तथा उनके संभावित उपयोग की जानकारी हासिल करना था। ईएसआईसी सनथ नगर की पहल उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक उपयोगी मॉडल बन सकती है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में ईएसआईसी का नेटवर्क सभी 33 जिलों में फैला है। राज्य में चार ईएसआईएस अस्पताल, 70 औषधालय, आठ शाखा कार्यालय और 10 डिस्पेंसरी-कम-ब्रांच ऑफिस संचालित हैं। ईएसआई योजना के तहत 20.47 लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों और 74.32 लाख से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। सनथ नगर परिसर में 800 बेड का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा 244 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है। परिसर में 159 आईसीयू बेड, 45 डायलिसिस बेड, 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और पांच उन्नत ओटी सूट हैं।

## ग्लास वॉल सिस्टम्स इंडिया का आईपीओ 8 सितंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 172-182 रुपये प्रति शेयर

**नई दिल्ली,एजेंसी।** ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार, 8 सितंबर को खुलेगा। इसमें निवेश करने के लिए निवेशक गुरुवार, 10 सितंबर 2026 तक बोली लगा सकते हैं। इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 172-182 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

कंपनी ने गुरुवार को मुंबई मे आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार, 8 सितंबर, 2026 को खुलेगा और गुरुवार, 10 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 172-182 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड के अनुसार 2 रुपये अंकित मूल्य वाले इस इश्यू में निवेशक न्यूनतम 82 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 82 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। कंपनी के शेयर 16 सितंबर, 2026 को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है। कंपनी के मुताबिक कुल इश्यूड, सबस्क्राइब और पेड-अप इक्विटी शेयर का कैपिटल 16,92,77,100 रुपये है, जो 2 रुपये फेस वैल्यू वाले

8,46,38,550 इक्विटी शेयरों में बंटी हुई है। सार्वजनिक घोषणा के अनुसार यह आईपीओ 60 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 2.02 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का मिश्रण होगा। नए शेयर से प्राप्त राशि में से 50 करोड़ रुपये का इस्तेमाल महाराष्ट्र के विले भगाड़ स्थित कंपनी की इकाई में प्रस्तावित पिछड़ेएकीकरण के तहत ग्लास प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने में किया जाएगा।

शेष राशि का इस्तेमाल सामान्य कामकाज के लिए होगा। ग्लास वॉल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड की योजना नए शेयरों से मिलने वाले लगभग 50 करोड़ रुपये (500 मिलियन रुपये) में से कुछ पैसों का इस्तेमाल कंपनी के विले भागड़ महाराष्ट्र वाली यूनिट में नया ग्लास प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए करने की है। वहीं, बाकी बचे पैसों को कंपनी की सामान्य जरूरतों (जनरल कॉरपोरेट) पर खर्च किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में स्थापित ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) भवन के बाहरी हिस्से के लिए समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। कंपनी का कारोबार भारत के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी है। इतना ही नहीं यह 2024 में रेवेन्यू के आधार पर कंपनी भारत की सबसे बड़ी फैसाड एक्सपोर्टर भी रही है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा ( यूपी ), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। ( संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी )